मानवता में व्यावहारिक अनुसंधान के उपरांत प्रस्तुत शोध प्रबंध

अनुसंधान का विषय- जनजातीय समुदाय और मानवता

शोधार्थी का नाम- विजय पाटिल

पंजीयन संख्या- HR/369/85 दिनांक- 26/01/2024

शोधार्थी का पता- सेंधवा जिला बड़वानी म.प्र.

शोध पर्यवेक्षक –
डॉ शेख शकील जलालुद्दीन प्रिंसिपल
पीएचडी गाईड

दिव्य प्रेरक कहानियाँ मानवता अनुसंधान केंद्र
DIVYA PRERAK KAHANIYAN HUMANITY RESEARCH CENTRE
An ISO 21001:2018 Certified Research Institution

Regd. Under Indian Trust Act 1882, Government of India

पंजीकृत कार्यालय- ठेकमा, जिला- आजमगढ़, उत्तर प्रदेश (भारत)

शोधार्थी घोषणा पत्र

मैं विजय पाटिल (शोधार्थी दिव्य प्रेरक कहानियाँ मानवता अनुसंधान केंद्र) यह घोषणा करता हूँ की प्रस्तुत शोध प्रबंध ‘’जनजातीय समुदाय एवं मानवता ” जो व्यावहारिक अनुसंधान का मूल भाग है तथा अप्रकाशित है। इस शोध प्रबंध (थिसिस)को प्रो.डॉ. शेख शकील जलालुद्दीन सर प्राचार्य नवलभाऊ प्रतिष्ठान महिला आर्ट एंड कॉमर्स महाविद्यालय अमलनेर महाराष्ट्र के मार्गदर्शन में हमने पूरा किया है। मैं यह घोषणा करता हूँ की इस शोध कार्य(थीसिस)में किसी प्रकार के साहित्यिक चोरी नहीं की गई है तथा इससे पहले किसी अन्य डिग्री डिप्लोमा के लिए उपयोग नहीं किया गया है। यह भी प्रमाणित करता हूँ की हमने अपना अनुसंधान कार्य दिव्य प्रेरक कहानियाँ मानवता अनुसंधान केन्द्र द्वारा प्रतिपादित सभी नियम व निर्देशों के तहत पूर्ण किया है।

दिनांक.....09/02/2025

शोधार्थी का हस्ताक्षर
विजय पाटिल वरिष्ठ शिक्षक
उच्च माध्य विद्या गवाड़ी
(जिला बड़वानी मप्र)

पर्यवेक्षक घोषणा पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिव्य प्रेरक कहानियाँ मानवता अनुसंधान केंद्र अंतर्गत "समाज सेवा और मानवता" विषय पर शोधार्थी ‘’श्री विजय पाटिल द्वारा किया गया प्रस्तुत अनुसंधान मूल व अप्रकाशित भाग है। इनके द्वारा मेरे निर्देशन में यह शोध कार्य (थिसिस)किया गया है एवं शोध प्रबंध साहित्यिक चोरी रहित, बहुत ही उत्कृष्ठ है तथा शोध प्रकाशन के लिए उपयुक्त है ।

वर्तमान में यह व्यवहारिक अनुसंधान कार्य समाज में सामाजिक समरसता, आपसी एकता, प्रेम, सहयोग, परोपकार तथा नैतिकता, मानवता युक्त सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में अति महत्वपूर्ण साबित होगा। इस तरह का अनुसंधान कार्य करना, अनुसंधान कर्ता की कार्य कुशलता व सच्ची मानवता के प्रति समर्पण को दर्शाता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि शोधार्थी ने अपना अनुसंधान कार्य **दिव्य प्रेरक कहानियाँ मानवता अनुसंधान केन्द्र** द्वारा प्रतिपादित सभी नियम व निर्देशों के तहत पूर्ण किया है ।

दिनांक……09/02/2025

पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर

Principal
Navalbhau Pratishthan's
Rukhaminitai Arts & Commerce
Mahila College Amalner

नाम .. डॉ शेख शकील जलालुद्दीन
पद नाम ..प्रिंसिपल (93091-54057)
पीएचडी गाईड
श्रीजगदीश प्रसादझबरमल टाइबरवाला विश्वविद्यालय (राजस्थान)

प्रस्तावना :— आधुनिक युग की खोज उपभोगवाद पर आधारित है। किन्तु आदिम इतिहास के संदर्भ में आदिम जनजातीय का अध्ययन करना भी आधुनिक समाज की आवश्यकता है। ये आदिम आदिवासी जनजाति जंगलों में निवास करती है, जंगल ही इनका जीवन है तथा आधुनिकता की चकाचौंध से कौसों दूर है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जनजाति अपने जंगली वातावरण में ही मदमस्त जीवन यापन करने के लिए बनी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मानवीय विकास का चक्र निरन्तर चलता रहता है। समाज का कर्तव्य है कि समाज का प्रत्येक प्राणी सुखी—सम्पन्न जीवन—यापन करें। इस हेतु सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। वर्तमान परिवेश में आदिवासी जनजाति समुदाय का विकास सरकार की प्रमुखता है। देश के सम्पूर्ण विकास में सभी समुदाय का सहयोग आवश्यक है, किसी एक समुदाय को छोड़कर देश का समग्र विकास नहीं किया जा सकता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि विश्व की अनेक मानव जातियों ने विकास का कदम एकसाथ रखा जिसमें से कुछ मानव जातियों ने अपना विकास परिष्कृत रूप से किया और आधुनिक प्रजातियों में आ गये। किन्तु आधुनिक युग में अनेक आदिम जाति विलुप्त हो गईं या विलुप्ति के कगार पर है, किन्तु भारतीय आदिम जनजाति ने अपने आपको विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रखा है जो कि भारतीय जनजातियों की प्रमुख विशेषता है।

पराधीनता के समय में जब अंग्रेजों ने इनके निवास स्थलों पर अतिक्रमण किया तो ये सीधे—सादे आदिवासियों ने अंग्रेजी सत्ता के विरूद्ध अपने परम्परागत हथियारों (तीर—धनुष, भाले) से लड़ाई लड़ी। ''बिरसा मुण्डा'' आदिवासी समुदाय ने आजादी की लड़ाई में नेतृत्व किया और अपनी साहसिक प्रवृत्ति का परिचय दिया। ये आदिवासी और जनजातियाँ जंगलों, नदी, नालों और जंगली जानवरों के बीच सदियों से सहचर करते आ रहे हैं। यदि कोई इनके क्षेत्रों में अतिक्रमण करें तो ये सीधे—सादे आदिवासी भी उग्र हो उठते हैं। ये आदिवासी समुदाय जो सदियों से जंगलों में रहते आ रहे हैं। वर्तमान में ये जनजाति अत्यंत पिछड़ी, गरीब, अभाव ग्रस्त और मुख्यधारा से विमुख है। भारतीय समाज में किसानों, दलितों, स्त्रियों, आदिवासियों और जनजातियों

का एक ऐसा विशाल समूह हमेशा से विद्वमान रहा है, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीति और सरकारी योजनाओं से हमेशा से ही वंचित और विकास से विमुख रहा है। सरकार ने पहले तो इन वंचित समूहों के विकास हेतु कोई खास योजना ही नहीं बनाई और यदि वर्तमान में इन समूहों को मुख्य धारा से जोड़ने की योजना बनाई भी गई तो सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ ये समूह नहीं उठा पा रहे हैं।

स्वदेशी – विदेशी मानव शास्त्रियों, समाज शास्त्रियों, भाषा शास्त्रियों तथा आदि के अनुसार आदिवासी शब्द की अवधारणा के विहंगावलोकन से लेकर उनके द्वारा निर्दिष्ट गुणधर्मों, विशिष्ट लाक्षणिकताओं एवं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए अब कुछ हद तक 'कौन हैं आदिवासी' की अवधारणा धीरे–धीरे स्पष्ट हो जाती है। आदिवासी समाज व संस्कृति के समग्र आकलन से पूर्व 'सभ्यता और संस्कृति' की अवधारणा को स्पष्ट कर लेना अति आवश्यक है। 'सभ्यता' शब्द 'सभा' शब्द में क्रमशः 'यत्', 'तल्' एवं 'टाप्' प्रत्ययों के योग से निष्पन्न है।

सभ्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है – व्यक्ति का गुण जो उसे किसी समाज, सभा, और देश के योग्य नागरिक बनाता है। अर्थात् व्यक्तियों का सामाजिक, नियमों और व्यवहारों को जानना, उसका पालन करना, समाज के अनुरूप ही आचरण करना और अनुशासन में बँधे रहना ही 'सभ्यता' है।

संस्कृति क्या है? उसको लेकर इसको कहीं पढ़ने में एक वाक्य आया था कि ''भूखा आदमी रोटी खाए यह प्रकृति है, अपनी रोटी में से दूसरे भूखे को दे, यह संस्कृति है, दूसरों की रोटी छीनकर खा जाए वह विकृति है। भारत में समाज शास्त्रियों, दर्शनशास्त्रियों, राजनीतिओं एवं शिक्षा विदों ने संस्कृति की विभिन्न परिभाषाएँ की है। डॉ. रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार –''संस्कृति एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन में छाया हुआ है। एक आत्मिक गुण है जो मनुष्य स्वभाव में उसी प्रकार व्याप्त है, जिस प्रकार फूलों में सुगंध और दूध में मक्खन। इसका निर्माण एक या दो दिन में नहीं होता, युगयुगान्तर में होता है।

हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानन्दन पतं लिखते हैं कि ''संस्कृति को मैं मानवीय पदार्थ मानता हूं, जिसमें हमारे जीवन के सूक्ष्म स्थलू दोनों धरा तलों के सत्यों

का समावेश तथा हमारे ऊर्ध्व चेतना शिखर का प्रकाश और समदिक जीवन की मानसिक अपत्यकाओं की छायाएँ हैं। उसके भीतर अध्यात्म, धर्म, नीति से लेकर सामाजिक रूढ़ि, रीति, तथा व्यवहारों का सौन्दर्य भी एक अन्तर सामंजस्य ग्रहण कर लेता हैं। संस्कृति को हमें अपने हृदय की शिराओं में बहने वाला मनुष्यत्व का रूधिर कहना चाहिए।

भारतीय संस्कृति साझा संस्कृतियों से निर्मित है। विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक हैं। भारत का आदिवासी समाज सदियों से अपनी विशिष्ट संस्कृति एवं परम्पराओं को बचाने में कामयाब रहा है। आदिवासी संस्कृति की भव्यता एवं दिव्यता के बयान से पूर्व गैर आदिवासी भारतीय संस्कृतियों के साथ के संबंधों का जिक्र भी आवश्यक है। अर्थात् आदिवासी समाज व संस्कृति के विहंगावलोकन के संदर्भ में आदिवासी और गैर आदिवासी समाजों के बीच इतिहास में क्या रिश्ता रहा है? इन सवालों पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। भारत भर में वर्तमान समय में आदिवासियों के लेकर धडल्ले के साथ साहित्य सृजन किया जा रहा है। उनमें से ज्यादातर लेखक या साहित्यकार तो गैर आदिवासी ही हैं। कुछ तो मात्र साहित्य निर्माण के लिए भी लिखने वाले लागे हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय साहित्य में आदिवासी समाज व संस्कृति का जो प्रतिबिम्ब मिलता है, वह न तो सम्पूर्ण है और न तो न्याय संगत ही है।

आज का दौर वैश्वीकरण का है। आज हर व्यक्ति अपने सपनों को साकार करना चाहता है। वैश्वीकरण के प्रतिरोध में आदिवासी साहित्य की अनुगूंज को भी समझने और जानने की दरकार है। जिसके लिए सबसे पहले हमें आदिवासी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति को बचाना होगा। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजक है।

प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक नोम चॉमस्की का मानना है कि 'वैश्वीकरण' का अर्थ अन्तर्राष्ट्रीय एकीकरण है। इस एकीकरण में भाषा की अहम् भूमिका होगी और जो भाषा व्यापक रूप में प्रयोग में रहेगी, उसी का स्थान विश्व में सुनिश्चित होगा।' इसमें कोई शक नहीं कि वैश्वीकरण ने शहरी जीवन स्तर में सुधार किया और उसे ऊँचा उठाया है, लेकिन हाल फिलहाल में भूमण्डलीकरण के विरोध में आवाज उठाई जा रही है जो समाज के ऐसे वर्ग से आती है जो तथाकथित जंगली हैं, असभ्य हैं, बर्बर हैं और मूल समाज का हिस्सा नहीं हैं। इनकी आवाज में ऐसी समस्या की पीड़ा है जिसने समाज के शिक्षितों को इनकी आवाज में आवाज मिलने को विवश किया है। सवाल उठता है कि ऐसी क्या वजह है जिसने इस समाज को भूमण्डलीकरण के विरोध में खड़ा किया है जिस वैश्वीकरण से सम्पूर्ण विश्व का लाभ हो रहा है, तरक्की हो रही है, उसके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, आदिवासी समाज उसका विरोध क्यों कर रहा है। भगवान ग्वाहड़े की पुस्तक ''आदिवासी मोर्चा'' में कविता ''वैश्वीकरण की असली शक्ल'' शीर्षक से ज्ञात हो जाता है कि आदिवासी समाज के लिए वैश्वीकरण की छवि नकारात्मक है। आदिवासी प्रकृति से जुड़े हुए हैं, उनकी आत्मा, उनके पूर्वज पेड़ों में बसते हैं, उनका जीवन, उनकी सम्पूर्ण दिनचर्या प्रकृति के आस–पास उसके साथ है, लेकिन वैश्वीकरण के कारण उनके क्षेत्र के पहाड़ टूट रहे हैं, झरने नालों में परिवर्तित हो रहे हैं।

जनजाति से आशय :– भारतीय समाज में जनजाति से आशय वन्य जाति, आदिवासी, वनवासी, आदिमजाति, गिरिजन आदि से है। ये जनजाति ऐसे लोगों का समुदाय है जो आज भी जंगलों में निवास करते हैं। प्राकृतिक साधनों से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। आधुनिक सभ्य समाज से दूर रहते हैं तथा शिक्षा, कृषि, उद्योग–धन्धे आदि से अपरिचित है। **भारत की जनगणना 1991 के अनुसार** :– ये अपने सीमित साधनों से केवल जीवित रहना ही सीख सके हैं और आज भी विज्ञान की इस चकाचौंध व सभ्यता की होड़ से अपरिचित ही है। ऐसे ही अपरिचित लोगों का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुसूचित आदिमजाति या जनजाति (ग्रामीण) के अन्तर्गत किया गया है।

भारतीय इतिहास में आदिवासी समूह का वर्णन प्राचीन समय से मिलता है। **डॉ. श्रीनाथ शर्मा के जनजातीय अध्ययन के अनुसार :–** ''भारतीय समाज में प्रौगेहासिक काल से लेकर आज तक आदि समूहों एवं वनवासियों का उल्लेख प्राप्त होता रहा है। वैदिक एवं उत्तर वैदिककाल तथा महाकाव्य काल में जनजातियों के नाम भी उल्लेखित है। जनजाति या आदिम जाति अथवा आदिवासी 'ट्राईब्स' शब्द का हिन्दी रूपान्तरण है। अंग्रेजी भाषा में ट्राइब शब्द का अर्थ कुटुम्ब है। राजनीतिशास्त्र में अविकसित समाज को ट्राइब्स कहते हैं। स्थान तथा काल के सम्बन्ध में भी ट्राइब शब्द भिन्न है जैसे, ''यूरोप में टुण्ड्रा प्रदेश के निवासी ऐस्किमों ही ट्राइब है तथा शेष दुनिया के लिये समग्र अफ्रीकी नीग्रो ही ट्राइब है। अर्थात् सिर्फ ताकतवर और विजेता ही है जो ट्राइब नहीं है।

भारतीय समाज में विभिन्न प्रजातियों का संगम हुआ है। यथा जब जनजातियों का अध्ययन किया जाता है तो यह शोधार्थी के समक्ष विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। कभी–कभी सभी आदिवासी को वनवासी समझ लिया जाता है, जबकि इनकी कई पीढ़ी पहले से ही शहर में आकर बस गई है। और शहरी वातावरण के अनुकूल हो गई है। तथा इनकी वंशावली आदिम आदिवासी ही है और ये सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जनजाति में भी शामिल है। किन्तु इनका वास्तविक व्यवहार आदिवासी जनजाति से भिन्न है। **वर्जीनियस खाखा के जनजातीय अध्ययन के अनुसार :–** भारत में जनजातियों की परिकल्पना मुख्य रूप से वृहद भारतीय समाज से उनके भौगोलिक और सामाजिक अलगाव के रूप में की जाती है। और इसमें उनके सामाजिक रूपान्तरण के चरण को ध्यान में नहीं रखा जाता है। यही कारण है कि सामाजिक रूपान्तरण के विभिन्न स्तरों पर समूहों और समुदायों का एक विस्तृत क्षेत्र जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया। इस तथ्य को देखते हुए कि जनजातियॉ वृहत्तर भारतीय समाज से अलग रहती रही हैं, अपने अधिवास के प्रदेश पर शासन में उनकी स्वायत्तता है। उनका भूमि, वन और अन्य संसाधनों पर नियंत्रण है और वे स्वयं के कानूनों, परंपराओं और रीति–रिवाजों से शासित है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में जनजाति की अपनी विशिष्ट पहचान है। ये भौगोलिक रूप से निश्चित भू–भाग (जंगल, पहाड़, गुफाओं) आदि में निवास करते हैं। समाजशास्त्री इन्हें वंचित वर्ग, समूह या समुदाय द्वारा सम्बोधित करते हैं। **हट्टन** ने इन्हें आदिमजाति नाम से सम्बोधित किया है। **जी.एस. घुरिये ने** इन जनजाति या आदिवासी समूह को ''पिछड़े हिन्दू'' कहा है। **श्यामाचरण दुबे के अनुसार :–** ''वास्तव में जनजाति'' व्यक्तियों का एक वह समूह है, जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में आवास या विचरण करता है। और जो किसी आदि पूर्वज को ही अपना उद्‌गम मानता हो तथा जिसकी एक सामान्य संस्कृति होती है, और जो आज भी आधुनिक सभ्यता के प्रभावों से परे है।

जनजाति सम्बन्धी परिभाषाऍ :–

इम्पीरियल गजेटियर के अनुसार :– ''जनजातीय परिवार या परिवारों का ऐसा समुदाय है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जो एक सामान्य बोली बोलते है, जो एक सामान्य भू–भाग पर रहने का दावा करता हो, और जो हमेशा अन्तर्विवाह नहीं करता, भले ही प्रारम्भकर्ता रहा हो।

मडौक के अनुसार :– ''यह एक सामाजिक समूह है, जिसकी एक अलग भाषा होती है तथा भिन्न संस्कृति एवं एक स्वतन्त्र राजनैतिक संगठन होता है।

गिलिन एवं गिलिन के अनुसार :– ''स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी समूह को जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा है।

जनजाति की विशेषताऍ :–

1. सामान्य भाषा :– प्रत्येक जनजाति की अपनी एक भाषा होती है, जिसके माध्यम से ये अपने अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। ये जनजातियॉ प्रायः स्थानीय बोलियों का प्रयोग करती है।

2. एक नाम :– प्रत्येक जनजाति अपने नाम से पहचानी जाती है। जनजाति के सदस्य अपने नाम से ही अपना परिचय प्रस्तुत करते हैं। जैसे – भील, भिलाला, बारेला आदि।

3. **निश्चित भू–भाग** :– जनजाति एक निश्चित भू–भाग में निवास करती है। एक निश्चित भू–भाग में रहने के कारण ही जनजातियों में सामान्य जीवन की विशेषताएँ विकसित हो जाती हैं। निश्चित भू–भाग जनजातियों की विशिष्ट पहचान हैं।

4. **सामान्य संस्कृति** :– प्रत्येक जनजाति अपनी विशिष्ट संस्कृति से जानी जाती हैं। किन्तु एक ही जनजाति के सभी सदस्यों में एक सामान्य संस्कृति अर्थात प्रथाएँ, रीति–रिवाज, नृत्य, धर्म, खान–पान, रहन–सहन होता है।

5. **परिवारों का एक समूह** :– सामान्यतः जनजातियों के अध्ययन से स्पष्ट होता है, कि प्रत्येक जनजाति एकसमान प्रजातीय तत्वों, एकसमान भाषा–संस्कृति वाले परिवारों का एक समूह है।

6. **नातेदारी का महत्व** :– ये सामान्यतः अपनी प्रथा, परम्परा, विश्वास आदि नातेदारों तक ही सीमित रखते हैं।

7. **अन्तर्विवाही समूह** :– जनजाति एक अन्तर्विवाही समूह है, प्रत्येक जनजाति इसका कड़ाई से पालन करते हैं।

8. **राजनैतिक संगठन** :– प्रत्येक जनजाति का एक मुखिया होता है, जो अपने समाज की परम्पराओं का पालन कराने, नियंत्रण रखने एवं नियमों के उल्लंघन करने पर दण्ड की व्यवस्था करता है।

9. **आर्थिक आत्मनिर्भरता** :– प्रत्येक जनजातीय समाज अपने आप में आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर रहता है। अपनी सभी आर्थिक आवश्यकताओं को ये स्वयं ही पूरा कर लेते हैं। शिकार, वनोपज संग्रहण तथा कृषि के माध्यम से जनजातियाँ अपनी दैनिक आवश्यकताएँ स्वयं पूर्ण करती हैं।

10. **सामान्य निषेध** :– जनजातियों में सामान्य निषेध के कारण ही खान–पान, विवाह, परिवार, व्यवसाय के प्रतिबंध बने हैं।

भारत युग युगान्तर से विभिन्न संस्कृतियों का संगम स्थल व सम्पर्क का अद्भुत संगम रहा है। इसीलिए भारत को विविधता में एकता का देश कहा जाता है। भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखने से यह पता चलता है कि ब्रितानी सल्तनत ने जहाँ–तहाँ प्रवेश किया, वहाँ के निवासियों को अपने से अलग करने हेतु उन्हें

'ने–टिव' या 'ट्रॉयल' की संज्ञा दे दी। उसके पूर्व यहाँ के समुदाय विशेष के लोगों को उनके अलग नामों से ही जाना जाता है। भारत के प्राचीन ग्रन्थों में इनका उल्लेख इनके अपने ही नामों उदाहरणार्थ भील, भिलाला, बारेला आदि के रूप में हुआ है। **राल्फ लिंटन** का कहना है कि सरलतम रूप में 'जनजाति' ऐसी टोलियों का एक समूह है, जिसका एक सान्निध्य वाले भूखण्ड अथवा भूखण्डों पर अधिकार हो और जो एकता की भावना संस्कृति में गहन समानता निरन्तर सम्पर्क तथा कतिपय सामुदायिक हितों में समानता से उत्पन्न हुई हो। मूल निवासियों में से वे व्यक्ति जिन्होंने आर्य सभ्यता को स्वीकार कर लिया। उन्हें आर्यों ने 'दास' कहा तथा अपने वर्णक्रम में चौथा स्थान दिया, किन्तु वे मूल निवासी जो आर्य संस्कृति से स्वयं को समाहित न कर सके, वे दुर्गम वनों में भाग गये। 'मूल निवासी जो हजारों वर्ष पूर्व आक्रान्ताओं के भय से दुर्गम वनों में शरण लेने को विवश थे – आज
''आदिवासी'' के नाम से जाने जाते हैं।

आदिवासी भारतीय समाज के अभिन्न अंग हैं, विश्व में शायद ही भारत ही ऐसा देश है, जिसकी मुख्य आबादी तो गैर–आदिवासी है, पर जिसकी आदिवासी आबादी सम्भवतः विश्व की किसी भी देश की आदिवासी आबादी से अधिक है। आदिवासी का शाब्दिक अर्थ है, आदिम युग में रहने वाली जातियाँ। आज का आदिवासी विमर्श अस्तित्व और अस्मिता का विमर्श है। यह ऐसा विमर्श है जिससे इस समुदाय की परम्परा रुढ़ियों, संस्कृति, अन्याय, अत्याचार, अपमान, शोषण आदि सभी कुछ का बयान हो रहा है। लोककला, संगीत, नृत्य, संस्कृति, भाषा, बोली, लिपि आदि विभिन्न धरातलों पर आदिवासी लेखन एक व्यापक विमर्श का हिस्सा बन रहा है। आदिवासी साहित्य जीवनवादी साहित्य है। इसमें जीवन के बुनियादी हकों से महरूम करने वाली व्यवस्था के विरोध की अभिव्यक्ति है। आदिवासी विमर्शकार राजाराम भादू ने भी कहा है कि ''आदिवासी साहित्य के उद्‌भव और परिप्रेक्ष्य निर्माण में मराठी और दलित साहित्य के सन्दर्भ को जोड़कर रखा गया है।

भारत के आदिवासियों में भील, भिलाला, बारेला की आबादी और संस्कृति काफी समृद्ध है। अब इनका सन्दर्भ प्राचीन सिन्धु घाटी की सभ्यता से भी जोड़ने पर विचार

और प्रयास किये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश के आदिवासियों में भील, भिलाला, बारेला की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। भील, भिलाला, बारेला परिश्रमी, सांस्कृतिक दृष्टि से सम्पन्न नृत्य गीत प्रिय, नैतिकता में आस्था रखने वाले लोग हैं। भील, भिलाला, बारेला में केन्द्रीय परिवार की व्यवस्था ही मान्य है। बच्चे बड़े होने पर समृद्ध और समर्थ होने पर अपनी गृहस्थी अलग बसा लेते हैं। कभी–कभार पर्व या किसी मांगलिक अवसर पर ही यह लोग अपने परिवार के साथ अपने पुश्तैनी घरों में आते हैं और आमोद–प्रमोद के अवसरों पर एक साथ एकत्र होकर उत्सव मनाते हैं। भील, भिलाला, बारेला की पारिवारिक व्यवस्था संयुक्त परिवार की नहीं है। इनमें एक पतित्व और एक पत्नीत्व की दाम्पत्य व्यवस्था ही प्रचलित है, किन्तु विधुर या विधवा हो जाने पर पुनर्विवाह किया जा सकता है। सामान्यतः भील, भिलाला, बारेला परिवार दाम्पत्य सम्बन्धों के मामलों में परम्परावादी और आदर्शोन्मुख दृष्टि के आग्रही हैं। परिवार में पितृसत्तात्मक व्यवस्था प्रचलित है।

भील, भिलाला, बारेला आदि का विश्वास है कि इनकी उत्पत्ति 'हंस' से हुयी है। इनके बारह गोत्र हैं – हसॅदॉक, किस्सू, मुर्मू, दुबु, हेम्बरम्, मारण्डी, सोरेन, वास्के, बसेरा, पेरिया, चौरे और बेड़िया अपने गोत्र के लिए इनमें अपार आत्मीयता रहती है। यह अपने गोत्र के प्रति सर्वस्व समर्पण की भावना रखते हैं। भील, भिलाला, बारेला में का महत्त्व सर्वाधिक है। यह पशु–पक्षियों को अत्यधिक पवित्र मानते हैं और यदि उनका कोई वध करता है तो इनकी ऐसी मान्यता है कि देवी–देवताओं की आत्माएँ उस व्यक्ति को दण्डित करती हैं। भील, भिलाला, बारेला आदि में निम्न प्रकार के विवाह प्रकारों का उल्लेख मिलता है –

(1) किरिग या किरिंग बहु, (2) जर्दी या घर जमाई, (3) किरिग जमाइन, (4) इतुत या मीर बोलोक, (5) मीर बोलोक, (6) टुकी दीपिका बापला, (7) संगा, (8) गो इंती बापला, (9) अथागीर बापला, (10) कुड़ाम बापला।

ग्रामीण न्याय व्यवस्था भील, भिलाला, बारेला की समाज व्यवस्था की धुरी है। गम्भीर अपराधों पर वह कड़े दण्ड देते हैं। यौन अपराधों में बिठलाहा उनकी अन्तिम दण्ड व्यवस्था है। जादू टोने में यह अत्यधिक विश्वास करते हैं। जादू–टोने का प्रयोग

रोग दूर करने, फसल बढ़ाने, उसकी रक्षा करने या दुश्मनों को नष्ट करने में की जाती है। इनका विश्वास है कि जंगल में चरते हुए पशुओं की रक्षा भी जादू टोने से सम्भव है। बलि इनके धार्मिक जीवन का मुख्य आधार है। देवी–देवताओं, पितरों की आत्माओं और अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिए या प्रायश्चित करने के लिए ये बलि का विधान करते हैं। ग्राम देवताओं की आत्माओं की भी भील, भिलाला, बारेला पूजा करते हैं। ये ग्राम देवता है – (1) जोहर एरा (स्त्री ग्राम देवी) (2) गोसाई एरा, (3) तुरुको मोरेको, (4) मारांग बुक, (5) पर गनैत। आदिवासियों के पर्व–त्योहार भी उनके जीवन की सरलता, निश्छलता और सांस्कृतिक आस्था को प्रतिबिम्बित करती हैं, वस्तुतः जनजीवन की सच्चरित्रता, आदर्शवाद, सेवा सद्‌भावना, सहयोग एवं सज्जनता से पूर्ण करने वाली प्रेरणाओं से भर देना, त्योहारों एवं पर्वों का मूल उद्‌देश्य है। ऐसे पर्वों में प्रमुख है, करमा, सरहुल, टुसु, गरवो, नवाई, भगोरिया, भोगली इत्यादि। करमा बिहार के छोटा नागपुर आदिवासियों का मुख्य पर्व है। यह पर्व भादो एकादशी को जब ये आदिवासी धान की रोपनी से निवृत्त होने के बाद उत्साह एवं सोल्लास मनाते हैं। अनेक क्रिया कर्म और मनौती के बादकरमकृपा की डाली लगायी जाती है और उसको गाड़कर परम्परागत तरीके से रीति के अनुसार उसके चारों ओर नृत्य गान करते हैं।

भील, भिलाला, बारेला का प्रमुख पर्व है। प्रकृति इस धरा पर अपनी नैसर्गिक छटा बिखेरती जन–जन को मोहित करती है। बसन्त के उत्सव के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। पतझड़ के उपरान्त वृक्ष व लतायें, नृत्य कोपलों से पूरित हो जाती हैं। सम्पूर्ण वन प्रदेश, प्रकृति की नैसर्गिक सुशमा से जाग्रत हो उठता है। खिले हुये पुष्पों की मादकता वातावरण में मिठास घोलने लगती है। सभी स्त्री–पुरुष मानों प्राकृतिक सुशमा से सम्मोहित हो जाते हैं। इन परिपूर्ण पुष्पों को लेने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही मदमस्त होकर मचल उठते हैं। आदिवासी अत्यन्त कठोरता से इस मान्यता का सम्मान करते हैं। प्रकृति की पूजा–अर्चना किए बगैर ये आदिवासी स्त्री–पुरुष कभी पुष्पों का उपयोग नहीं करते हैं। ये आदिवासी प्रकृति देवी को जयस–एरा या जगर बूटी के नाम से पूजन अर्चन करते हैं। इस पर्व को मनाने के लिए आदिवासी महीनों से तैयारी करते हैं।

जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न क्षेत्रों से नियोजित आदिवासी इस अवसर पर निश्चित रूप से घर वापस चले आते हैं। इस अवसर पर नई मिट्टियों से घर को लीपा जाता है, मकानों को विभिन्न प्रकार से सजाते हैं। इस अवसर पर आदिवासी पुरुषों के द्वारा केकड़ा और मछली पकड़ा जाता है। वही स्त्रियों के द्वारा 'शील' की पत्तियाँ तोड़ी जाती हैं। रात में केकड़ा और मछली को इमली में भिगोकर उसके रस में पकाया जाता है। इसके बाद बनाये गये खाद्य पदार्थों पूर्वजों को अर्पित किये जाते हैं। तब सब मिलकर भोजन करते हैं। दूसरे दिन सभी उपवास करते हैं जिसे 'कटक' कहा जाता है। इस पूजा के बाद पूजा–पाठ सम्पन्न होता है। सभी आदिवासी शाल के पत्तों पर अपने बंधु–बाँधवों के साथ भोजन करते हैं। पर्व के तीसरे और अन्तिम दिन ये आदिवासी जंगलों से शाल के फूल और तिलय की डाली काटकर लाते हैं। पूजा–पाठ के द्वारा शाल, फूल और तिलय देवी–देवताओं को अर्पित किया जाता है और मुर्गी की बलि दी जाती है।

आदिवासियों के अन्य पर्व जैसे भीलों के द्वारा की जाने वाली भीरलदेव पूजा (सर्पपूजा), इन्दल पर्व (इन्द्र पूजा), गरबो (दिवाली) के समय पर्व में परिगणित किया जा सकता है। आदिवासियों का जीवन परिप्रेक्ष्य और पर्व विधान उनकी आस्था के विविध आयामों को उद्घाटित करते हैं। सच्चे अर्थ में यह आदिवासी सहज, सरल, निश्कपट ढंग से इन पर्वों के द्वारा अपनी परम्परागत आस्था को प्रदर्शित करता है। भील, भिलाला, बारेला के परिवार एकल ही क्यों न हों, इनमें भावनात्मक सम्बन्ध अत्यन्त दृढ़ होता है और जीवन–पर्यन्त इस सम्बन्ध को निबाहते हैं। पति–पत्नी के प्रगाढ़ सम्बन्ध और प्रेम की अभिव्यक्ति उनके हृदयग्राही गीत में देखने को मिलती है।

''जेमन खिजूर सकाम वाडूजू रुकूआ
आलाक जड़ो लेका बो तोलेन बालाड़–बायान।''

अर्थात् जिस प्रकार एक खजूर का पत्ता वृक्ष से टूटकर कभी नहीं गिरता है, स्वर्णलता जैसे सदैव लिपटी रहती है, उसी प्रकार हम लोगों का दिल भी जीवन–पर्यन्त अलग नहीं हो सकता है। यह साहित्य केवल शब्दबद्ध रचना नहीं, बल्कि विभिन्न मुद्दों पर बेबाकी से शोषित, निर्बल, उपेक्षित, सर्वहारा, बहिष्कृत एक वर्ग की आवाज उठाने

वाला प्रतिबद्ध परिवर्तन कामी और संकल्पित प्रतिबद्ध साहित्य है। इसमें अवरोध का तेवर है। प्रतिशोध का जबरदस्त माद्दा है। अस्वीकार का अपार साहस है। स्वीकार की मौन अभिव्यक्ति है। सम्पूर्ण जीवन अनुभव की पूँजी है।

साहित्य की समीक्षा :–

राजपूत उदय सिंह (2008) ने अपने लेख में बताया कि आदिवासी समुदाय अनेक समस्याओं से जुझ रहे हैं। गरीबी, बीमारी, भुखमरी, बरोजेगारी और पलायन की मार झेल रहे आदिवासी समुदाय के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना एक सहारा बनकर उभरी है। उल्लेखनीय है कि, मध्यप्रदेश की 21.1 प्रतिशत जनसंख्या आदिवासी समुदाय की है, जो अनेक समस्याओं का सामना करते हुए अभावपूर्ण जीवन जी रहे हैं। रोटी के अभाव में भूखे पेट सोना, इलाज के अभाव में अकाल ही काल की गोद में समा जाना आदिवासी क्षेत्रों की कड़वी सच्चाई है।

गौतम नीरज कुमार (2011) ने अपने लेख में बताया कि जनजातीय समुदाय के विकास के लिए मछली पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय हैं तथा इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती हैं। इस प्रकार इस व्यवसाय को आसानी से शुरू किया जा सकता हैं, क्योंकि अधिकांश जनजातीय समुदाय ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और इन जनजातीय समुदाय कि स्थिति अत्यंत दयनीय है। ये जनजाति गरीब, बेरोजगार और अशिक्षित होने के कारण समाज के सम्पन्न वर्ग द्वारा बंधुआ मजदूर के रूप में शोषण करते हैं। सरकार द्वारा इनके आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान एवं स्वरोजगार के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की गयी हैं। जिसमें मछली पालन महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया गया हैं।

जैन अलका एवं शर्मा अर्चना (2013) ने अपने लेख में बताया कि भुखमरी की शिकार दुनिया की कुल आबादी का 25 प्रतिशत हिस्सा भारत में निवास करता हैं तथा 24 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। बेरोजगारी की स्थिति तो

बहुत दयनीय है। शहरी क्षेत्र में जहाँ शिक्षित तथा औद्योगिक बेरोजगारी पाई जाती है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी एवं प्रछन्न बेरोजगारी पाई जाती हैं। एक अनुमान के अनुसार कृषि कार्य में लगी कुल श्रम शक्ति का लगभग 17 प्रतिशत भाग प्रछन्न बेरोजगारी का हैं। आज भी कई योजनाएं जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्णजयंती रोजगार योजना, आदि योजनाएं चलाई जा रही हैं।

सिंह विकास कुमार (2014) ने अपने लेख में बताया कि अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी ये पलायन के तीन प्रमुख कारण है। गाँवों में न शिक्षा का माहोल है और न ही रोजगार का कोई साधन। इस कारण लोग पलायन को विवश हो जाते है और ग्रामीणों को आशा रहती है कि उन्हें महानगरों में जीवन की सभी सुविधाएँ उपलब्ध हो पाएगी महानगरों का दिवास्वप्न ही उन्हें गाँवों से शहरों की ओर भटकाता है। अगर मनरेगा के तहत सभी लोगों को उचित व योग्यता के लायक रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए, तो लोग अपने घरों को छोडकर बाहर के राज्यों में पलायन नहीं करेंगे। इससे उनकी सभ्यता व संस्कृति बचेगी साथ ही उनके पूरे समाज का विकास होगा।

शोध अध्ययन के उद्देश्य :–

1. बड़वानी जिले के पिछड़ी आदिवासी जनजातिय समुदाय की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. बड़वानी जिले के पिछड़ी आदिवासी जनजातिय समुदाय के विकास के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित योजनाओं का विस्तृत अध्ययन करना।
3. बड़वानी जिले के पिछड़ी आदिवासी जनजातिय समुदाय की आय एवं उनके रोजगार सृजन में शासकीय योजनाओं की भूमिका का अध्ययन करना।
4. बड़वानी जिले के पिछड़ी आदिवासी जनजातिय के आर्थिक, सामाजिक स्थिति में शासकीय योजनाओं का प्रभाव का अध्ययन करना।
5. बड़वानी जिले के पिछड़ी आदिवासी जनजातिय के लिए शासन द्वारा चलाई गई योजनाओं से उत्पन्न समस्या और उनका समाधान पर सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पना

1. बड़वानी जिले के पिछड़ी आदिवासी जनजातिय के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में राज्य शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है।

2. बड़वानी जिले के पिछड़ी आदिवासी जनजातिय समुदाय पर शासन द्वारा संचालित योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

3. बड़वानी जिले के पिछड़ी आदिवासी जनजाति की आय में वृद्धि और रोजगार का सृजन हो रहा है।

4. बड़वानी जिले के पिछड़ी आदिवासी जनजातिय समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

शोध प्रविधि :– प्रस्तुत अध्ययन को पूरा करने के लिए निदर्शन विधियों में सें दैव निदर्शन विधि का उपयोग किया गया। प्रस्तावित शोध हेतु मैंने मध्यप्रदेश के धार जिले का चयन किया गया हैं तथा प्रस्तुत शोध अध्ययन में धार जिले की पिछड़ी जनजातीय समुदाय के विकास में शासकीय योजनाओं की भूमिका का अध्ययन किया गया हैं। इस हेतु मैं अध्ययन हेतु बड़वानी जिले की 09 तहसील में से 04 तहसील :– सेंधवा निवाली, पानसेमल, बड़वानी का चयन किया गया हैं। इन 04 तहसीलों में से 20 गाँवों का चयन निदर्शन विधि से किया गया और इन गाँवों से जनजातीय समुदाय के 20–20 हितग्राही का चयन कर कुल 400 हितग्राही का अध्ययन किया गया। संक्षेप में कहा जाए तो बड़वानी जिले की कुल जनसंख्या 13,85,659 में से जनजातीय समुदाय की कुल 2,22,814 जनसंख्या जिले में निवास करती हैं। इन जनजातीय समुदाय की कुल जनसंख्या में से जनजातीय समुदाय के 400 हितग्राही का चयन निदर्शन आकार विधि से किया गया हैं।

समंको का विश्लेषण

पिछड़ी जनजातीय समुदाय की आयु संरचना के आधार पर विश्लेषण –: किसी भी समाज में व्यक्ति की स्थिति एवं भूमिका के निर्धारण में आयु वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान होता हैं। आयु के आधार पर ही किसी समुदाय, संस्था या समाज के सदस्यों को भिन्न–भिन्न वर्गो में बाँटा जाता हैं। आयु व्यक्ति के शारिरीक एवं मानसिक स्थिति तथा व्यक्तित्व को निर्धारित एवं प्रभावित करती हैं। व्यक्ति एक निश्चित आयु के पश्चात् ही विवाह, व्यवसाय, उत्तरदायित्व का निर्वाहन, सामाजिक संबंध एवं आर्थिक दशाओं से अनुकूल करता हैं। अतः आयु का सामाजिक–संरचना में महत्वपूर्ण स्थान हैं। इस प्रकार पिछड़ी जनजातीय समुदाय की आयु के संबंध में जो तथ्य प्राप्त हुए हैं, उन्हें अग्र तालिका में दर्शाया गया हैं

पिछड़ी जनजातीय समुदाय की आयु के आधार पर वर्गीकरण

आयु	आवृति	प्रतिशत
25 वर्ष से कम	98	24.5
25 से 30 वर्ष	107	26.8

30 से 35 वर्ष	63	15.8
35 से 40 वर्ष	72	18.0
40 वर्ष से अधिक	60	15.0
कुल	**400**	**100.0**

स्त्रोत :– स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

आरेख क्रमांक – पिछड़ी जनजातीय समुदाय की आयु के आधार पर वर्गीकरण

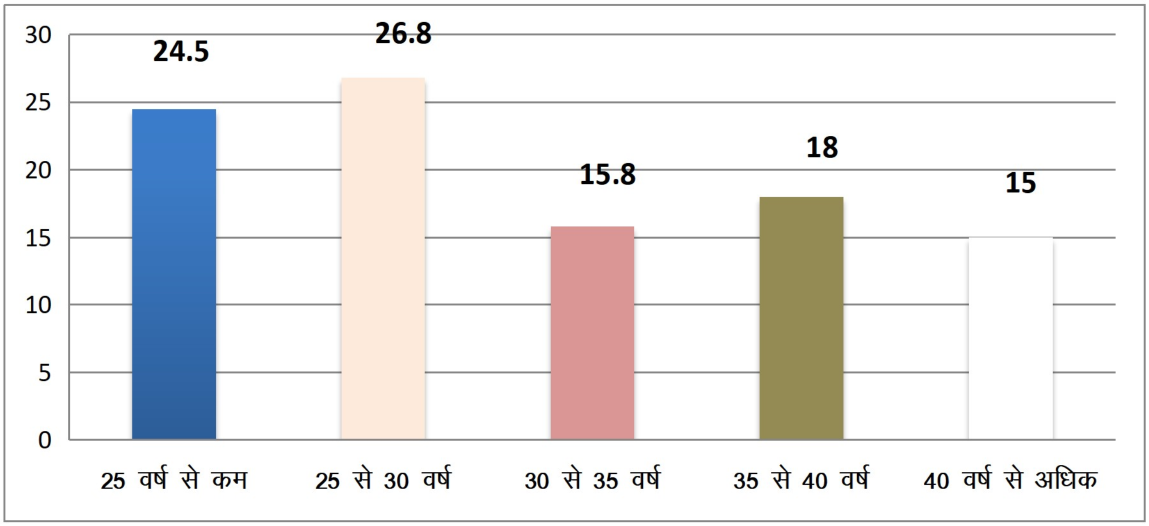

उपर्युक्त अध्ययन हेतु संकलित प्राथमिक समंकों को परिवार में मुखिया की आयु के आधार पर विश्लेषित किया गया हैं समंकों के विश्लेषण से यह पता चला हैं कि ग्रामीण उत्तरदाताओं में सर्वाधिक 26.8 प्रतिशत हैं, जिनकी आयु 25 से 30 वर्ष हैं। एवं 40 वर्ष से अधिक आयु वाले उत्तरदाताओं का 15 प्रतिशत है। अतः विश्लेषण

से स्पष्ट हुआ है कि सर्वेक्षित उत्तरदाताओं में सर्वाधिक 26.8 प्रतिशत हैं, जिनकी आयु 25 से 30 वर्ष है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय के लिंग के आधार पर विश्लेषण –: पिछड़ी जनजातीय समुदाय के लिंग के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें अग्र ता. में दर्शाया गया है

पिछड़ी जनजातीय समुदाय के लिंग के आधार पर वर्गीकरण

लिंग	आवृति	प्रतिशत
पुरूष	211	52.8
महिला	189	47.3
कुल	**400**	**100.0**

स्त्रोत :– स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

उपर्युक्त तालिका में पिछड़ी जनजातीय समुदाय के विकास में शासकीय योजनाओं की भूमिका का अध्ययन हेतु संकलित प्राथमिक समंकों का विश्लेषण किया गया है। समंकों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में सर्वेक्षित जनजातीयों में सर्वाधिक 52.8 प्रतिशत संख्या पुरूषों की है जो कि सबसे ज्यादा है। तथा 47.3 प्रतिशत संख्या महिलाओं की है, एवं पुरूषों की तुलना में महिलाओं की संख्या सबसे कम है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय के परिवार के स्वरूप के आधार पर विश्लेषण –: पिछड़ी जनजातीय समुदाय के परिवार के स्वरूप के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें अग्र तालिका में दर्शाया गया है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय के परिवार का स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण

परिवार का स्वरूप	आवृति	प्रतिशत
एकांकी परिवार	211	52.8
संयुक्त परिवार	189	47.3

कुल	**400**	**100.0**

स्त्रोत :— स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

परिवार का स्वरूप :— परिवार का आकार भी व्यक्ति के जीवन स्तर को प्रभावित करता है क्योंकि संयुक्त परिवार में काम करने वाले सदस्यों की संख्या अधिक होती है तो परिवार का जीवन स्तर भी अच्छा होता है एवं परिवार में काम करने वाले सदस्यों की संख्या कम है तो परिवार के सदस्यों पर इसका प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।उपर्युक्त अध्ययन हेतु संकलित प्राथमिक समंकों को परिवार का स्वरूप के आधार पर विश्लेषित किया गया हैं समंकों के विश्लेषण से यह पता चला हैं कि ग्रामीण जनजातीयों में सर्वाधिक 52.8 प्रतिशत हैं, जो कि संयुक्त परिवार के हैं। एवं एकांकी परिवार के जनजातीयों का 47.3 प्रतिशत है। अतः विश्लेषण से स्पष्ट हुआ है कि सर्वेक्षित जनजातीयों में सर्वाधिक 52..8 प्रतिशत हैं, एवं यह संयुक्त परिवार वाले है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय के मुख्य व्यवसाय के आधार पर विश्लेषण —: पिछड़ी जनजातीय समुदाय के मुख्य व्यवसाय के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें अग्र तालिका में दर्शाया गया है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय के मुख्य व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण

व्यवसाय	आवृति	प्रतिशत
कृषि	176	44
मजदूरी	127	31.8
अशासकीय नौकरी	73	18.3
शासकीय नौकरी	5	1.3
व्यवसाय (धंधा)	19	4.8
कुल	**400**	**100.0**

स्त्रोत :— स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

आरेख क्रमांक – पिछड़ी जनजातीय समुदाय के मुख्य व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण

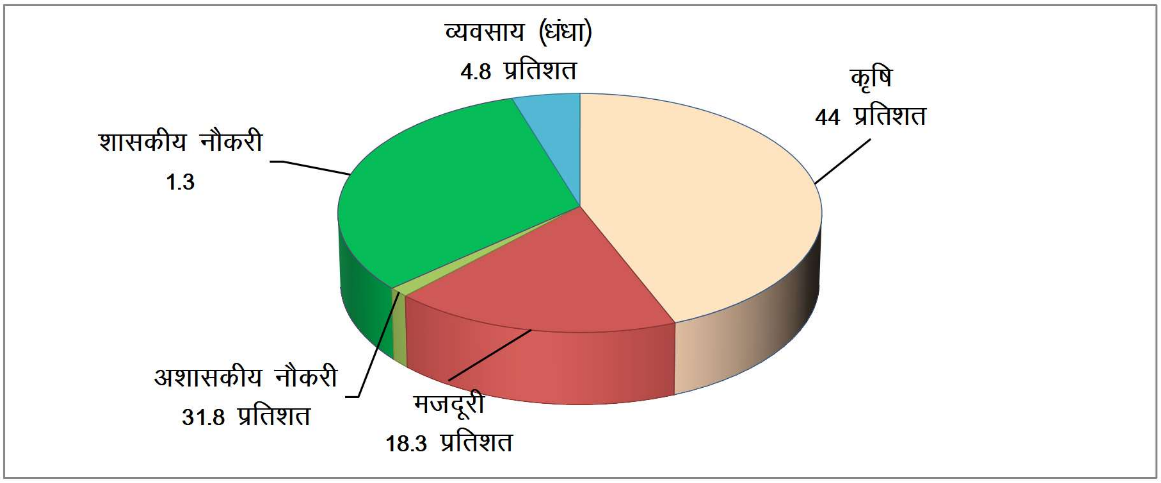

उपर्युक्त अध्ययन हेतु संकलित प्राथमिक समंकों को मुख्य व्यवसाय के आधार पर विश्लेषित किया गया हैं समंकों के विश्लेषण से यह पाया गया हैं कि ग्रामीण जनजातीयों में सर्वाधिक 44 प्रतिशत हैं, जो कि कृषि कार्य करते हैं। साथ ही शासकीय नौकरी करने वाले पिछड़ी जनजातीयों का 1.3 प्रतिशत है। अतः विश्लेषण से स्पष्ट हुआ है कि सर्वेक्षित जनजातीयों में सर्वाधिक 44 प्रतिशत हैं, एवं यह पिछड़ी जनजाती कृषि कार्य करते है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय की वैवाहिक स्थिति के आधार पर विश्लेषण –: विवाह से वैयक्तिक स्तर पर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संतोष प्राप्त होता हैं, तो व्यापक सामूहिक स्तर पर इससे समूह और संस्कृति के अस्तित्व निर्वाह में सहयोग मिलता हैं। किसी समाज में व्यक्ति की वैवाहिक–स्थिति अन्य अविवाहित व्यक्तियों की अपेक्षा उसके महत्व को प्रदर्शित करती हैं। समाज की निरन्तरता बनाये रखने लिए मानव उत्पत्ति प्राथमिक आवश्यकता हैं, जो विवाह पर निर्भर हैं। पिछड़ी जनजातीय समुदाय की वैवाहिक स्थिति के संबंध में जो तथ्य प्राप्त हुए हैं, उन्हें अग्र तालिका में दर्शाया गया हैं

पिछड़ी जनजातीय समुदाय की वैवाहिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण

वैवाहिक स्थिति	आवृति	प्रतिशत

विवाहित	213	53.3
अविवाहित	187	46.8
कुल	**400**	**100.0**

स्त्रोत :– स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

वैवाहित स्थिति – किसी भी समाज में व्यक्ति की विवाहिक स्थिति अन्य अविवाहित व्यक्यिों की अपेक्षा उसके महत्व को प्रदर्शित करता है। सामान्य रूप से यह कहा जाता है कि विवाहित व्यक्ति की सामाजिक स्थिति अविवाहित व्यक्ति की तुलना में अच्छी होती है क्योंकि सामाजिक दृष्टि से विवाहित व्यक्ति अनुभवी एवं परिपक्व माने जाते है। उपरोक्त तालिका में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली पिछड़ी जनजाती की वैवाहिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत कर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित ग्रामीण जनजातीयों में सर्वाधिक 53.3 प्रतिशत संख्या विवाहित है एवं यह जनजाती कृषि कार्य करते है, जो कि सबसे ज्यादा है। साथ ही 46.8 प्रतिशत संख्या अविवाहित है जो कि कृषि कार्य करते है, एवं विवाहित की तुलना में अविवाहित की संख्या सबसे कम है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय के मकान के स्वरूप के आधार पर विश्लेषण –: पिछड़ी जनजातीय समुदाय के मकान के स्वरूप के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें अग्र तालिका में दर्शाया गया है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय के मकान का स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण

मकान का स्वरूप	आवृति	प्रतिशत
कच्चा	151	37.8
पक्का	183	45.8
अर्द्ध–पक्का	66	16.5
कुल	**400**	**100.0**

स्त्रोत :– स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

आरेख क्रमांक – पिछड़ी जनजातीय समुदाय के मकान का स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण

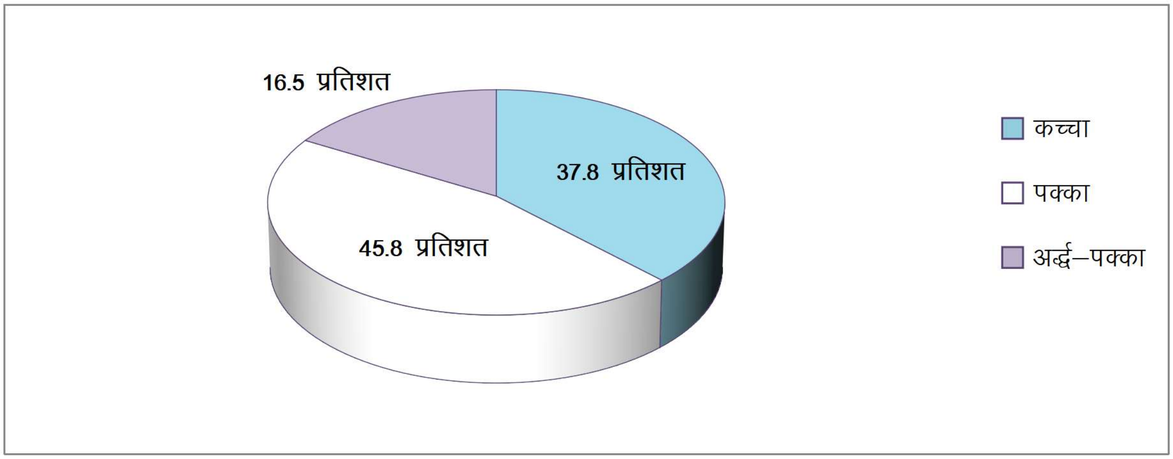

उपरोक्त तालिका में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली पिछड़ी जनजातीयों के मकान के स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत कर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित ग्रामीण जनजातीयों में सर्वाधिक 45.8 प्रतिशत जनजातीयों का मकान पक्का है, जो कि सबसे ज्यादा है। साथ ही 16.5 प्रतिशत संख्या जनजातीयों का मकान अद्ध–पक्का है, जो कि सबसे कम है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय की कुल कृषि योग्य भूमि के आधार पर विश्लेषण –: पिछड़ी जनजातीय समुदाय की कुल कृषि योग्य भूमि के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें अग्र तालिका में दर्शाया गया है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय की कुल कृषि योग्य भूमि के आधार पर वर्गीकरण

कृषि योग्य भूमि	आवृति	प्रतिशत
5 से कम बीघा	129	32.3
5 से 10 बीघा	99	24.8
10 से 15 बीघा	80	20.0
15 से 20 बीघा	62	15.5
20 से बीघा से अधिक	30	7.5

कुल	**400**	**100.0**

स्त्रोत :— स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

आरेख क्रमांक — पिछड़ी जनजातीय समुदाय की कुल कृषि योग्य भूमि के आधार पर वर्गीकरण

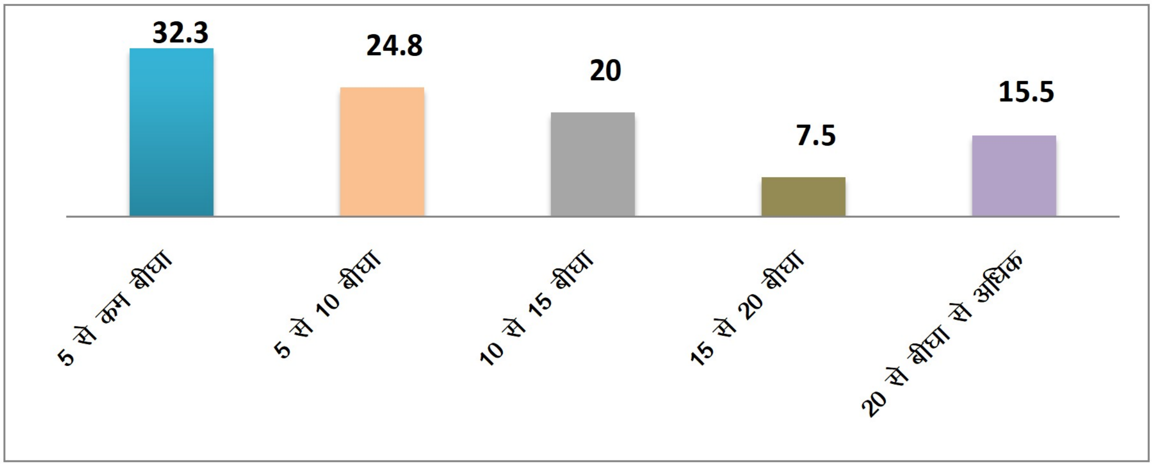

उपरोक्त तालिका में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली पिछड़ी जनजातीयों की कुल कृषि योग्य भूमि के आधार पर वर्गीकृत कर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित ग्रामीण जनजातीयों में सर्वाधिक 32.3 प्रतिशत कृषि कार्य करने वाले जनजातीयों का कहना है कि कुल कृषि योग्य भूमि 5 बीघा से कम है जो कि सबसे ज्यादा है। साथ ही 7.5 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि कुल कृषि योग्य भूमि 15 से 20 बीघा तक है, जो कि सबसे कम है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय के सिंचाई के साधन के आधार पर विश्लेषण —: पिछड़ी जनजातीय समुदाय के सिंचाई के साधन के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें अग्र तालिका में दर्शाया गया है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय के सिंचाई के साधन के आधार पर वर्गीकरण

सिंचाई के साधन	आवृति	प्रतिशत
पम्प सैट	147	36.8
नहर	86	21.5

कुऑ	70	17.5
फव्वारे से सिंचाई	66	16.5
तालाब	31	7.8
कुल	400	100.0

स्त्रोत :— स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

आरेख क्रमांक — पिछड़ी जनजातीय समुदाय के सिंचाई के साधन के आधार पर वर्गीकरण

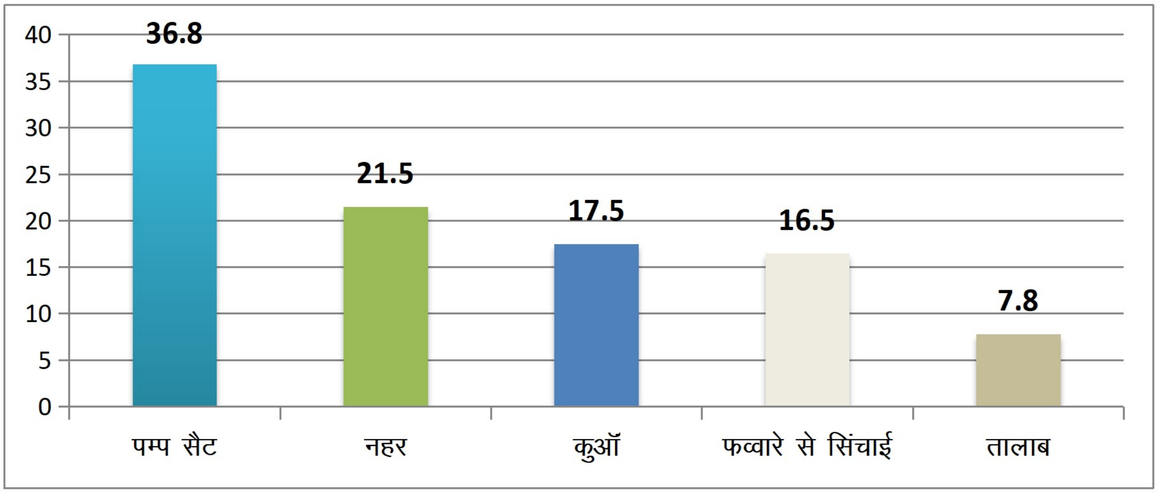

उपरोक्त तालिका में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली पिछड़ी जनजातीयों के सिंचाई के साधन के आधार पर वर्गीकृत कर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित ग्रामीण जनजातीयों में सर्वाधिक 36.8 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि खेतों में सिंचाई करने के लिए पम्प सैट का उपयोग करते है जो कि सबसे ज्यादा है। साथ ही 7.8 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि खेतों में सिंचाई करने के लिए तालाब का उपयोग करते है, जो कि सबसे कम है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय के लिए सरकार ने जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न योजनायें बनाई हैं के आधार पर विश्लेषण —: पिछड़ी जनजातीय समुदाय के लिए सरकार ने जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न योजनायें बनाई हैं के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें अग्र तालिका में दर्शाया गया है।

सरकार ने जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न योजनायें बनाई हैं के आधार पर वर्गीकरण

योजनायें बनाई	आवृति	प्रतिशत
हां	211	52.75
नहीं	189	47.25
कुल	**400**	**100.0**

स्त्रोत :– स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

उपरोक्त तालिका में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली पिछड़ी जनजातीयों को सरकार ने जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न योजनायें बनाई हैं के आधार पर वर्गीकृत कर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित ग्रामीण जनजातीयों में सर्वाधिक 52.75 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि सरकार द्वारा जनजातीयों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई गई है जिनका उपयोग आज पिछड़ी जनजाती कर रही है जो कि सबसे ज्यादा है। साथ ही 47.25 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि सरकार द्वारा जनजातीयों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं नहीं बनाई गई है जो कि आज भी पिछड़ी जनजातीयों को लाभ नहीं मिल रहा है, जो कि सबसे कम है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय के लिए सरकार ने जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न योजनायें बनाई हैं यदि हाँ तो कौन–कौन सी योजनायें है के आधार पर

विश्लेषण –: पिछड़ी जनजातीय समुदाय के लिए सरकार ने जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न योजनायें बनाई हैं यदि हाँ तो कौन–कौन सी योजनायें है के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें अग्र तालिका में दर्शाया गया है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय के लिए सरकार ने जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न योजनायें बनाई हैं यदि हाँ तो कौन–कौन सी योजनायें है के आधार पर वर्गीकरण

योजनायें	आवृति	प्रतिशत
प्रधानमंत्री ग्रामीन आवास योजना	95	23.8
मनरेगा योजना	92	23.0
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	71	17.8
राष्ट्रीय ग्रामीण आजिवीका मिशन योजना	73	18.3
अन्य योजनाए	69	17.3
कुल	**400**	**100.0**

स्त्रोत :– स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

आरेख क्रमांक – पिछड़ी जनजातीय समुदाय के लिए सरकार ने जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न योजनायें बनाई हैं यदि हाँ तो कौन–कौन सी योजनायें है के आधार पर वर्गीकरण

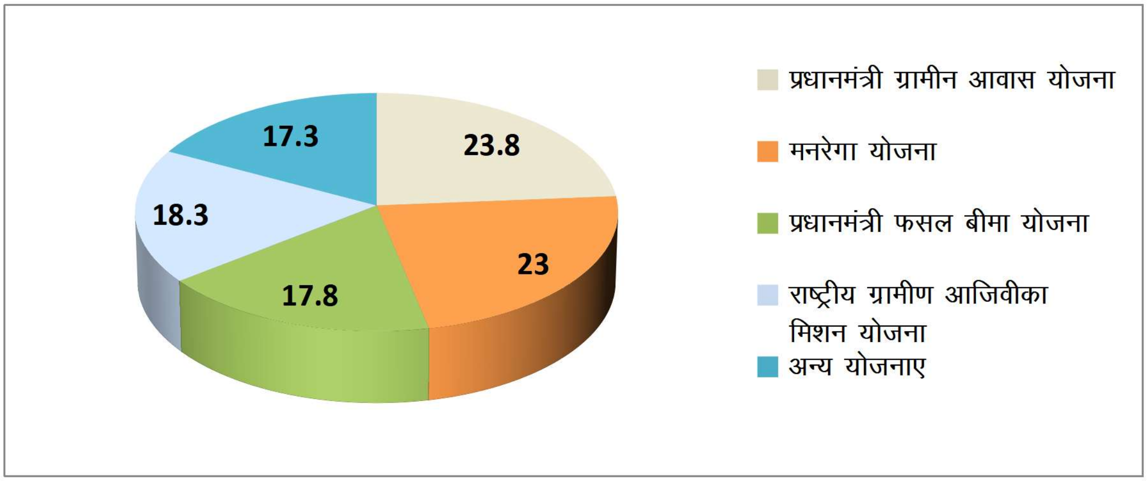

उपरोक्त तालिका में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली पिछड़ी जनजातीयों को सरकार ने जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न योजनायें बनाई हैं के आधार पर वर्गीकृत कर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित ग्रामीण जनजातीयों में सर्वाधिक 23.8 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि सरकार द्वारा जनजातीयों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं में से प्रधानमंत्री ग्रामीन आवास योजना का लाभ मिल रहा है जो कि सबसे ज्यादा है। साथ ही 17.3 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि सरकार द्वारा जनजातीयों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं में से अन्य योजनाओं का लाभ मिल रहा है जो कि आज भी पिछड़ी है, जो कि सबसे कम है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय के परिवार के किसी सदस्य ने इन जनजातियों के विकास योजनाओं का लाभ लिया है के आधार पर विश्लेषण –: पिछड़ी जनजातीय समुदाय के परिवार के किसी सदस्य ने इन जनजातियों के विकास योजनाओं का लाभ लिया है के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें अग्र तालिका में दर्शाया गया है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय के परिवार के किसी सदस्य ने इन जनजातियों के विकास योजनाओं का लाभ लिया है के आधार पर वर्गीकरण

योजनाओं का लाभ लिया है	आवृति	प्रतिशत

हां	296	74
नहीं	104	26
कुल	**400**	**100.0**

स्त्रोत :– स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

उपरोक्त तालिका में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली पिछड़ी जनजातीयों के परिवार के किसी सदस्य ने इन जनजातियों के विकास योजनाओं का लाभ लिया है के आधार पर वर्गीकृत कर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित ग्रामीण जनजातीयों में सर्वाधिक 74 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि सरकार द्वारा जनजातीयों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का लाभ लिया है जो कि सबसे ज्यादा है। साथ ही 26 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि सरकार द्वारा जनजातीयों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का लाभ नही लिया है, जो कि सबसे कम है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय के परिवार के किसी सदस्य ने इन जनजातियों के विकास योजनाओं का लाभ लिया है यदि हाँ, तो किस योजना का लाभ मिला है के आधार पर विश्लेषण –: पिछड़ी जनजातीय समुदाय के परिवार के किसी सदस्य ने इन जनजातियों के विकास योजनाओं का लाभ लिया है यदि हाँ, तो किस योजना का लाभ मिला है के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें अग्र तालिका में दर्शाया गया है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय के परिवार के सदस्य ने जनजातियों के विकास योजनाओं का लाभ लिया है यदि हाँ, तो किस योजना का लाभ मिला है के आधार पर वर्गीकरण

योजना का लाभ मिला है	आवृति	प्रतिशत
प्रधानमंत्री ग्रामीन आवास योजना से	153	38.3
मनरेगा योजना से	79	19.8
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से	119	29.8
राष्ट्रीय ग्रामीण आजिवीका मिशन योजना से	49	12.3

कुल	**400**	**100.0**

स्त्रोत :– स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

आरेख क्रमांक – पिछड़ी जनजातीय समुदाय के परिवार के किसी सदस्य ने इन जनजातियों के विकास योजनाओं का लाभ लिया है यदि हाँ, तो किस योजना का लाभ मिला है के आधार पर वर्गीकरण

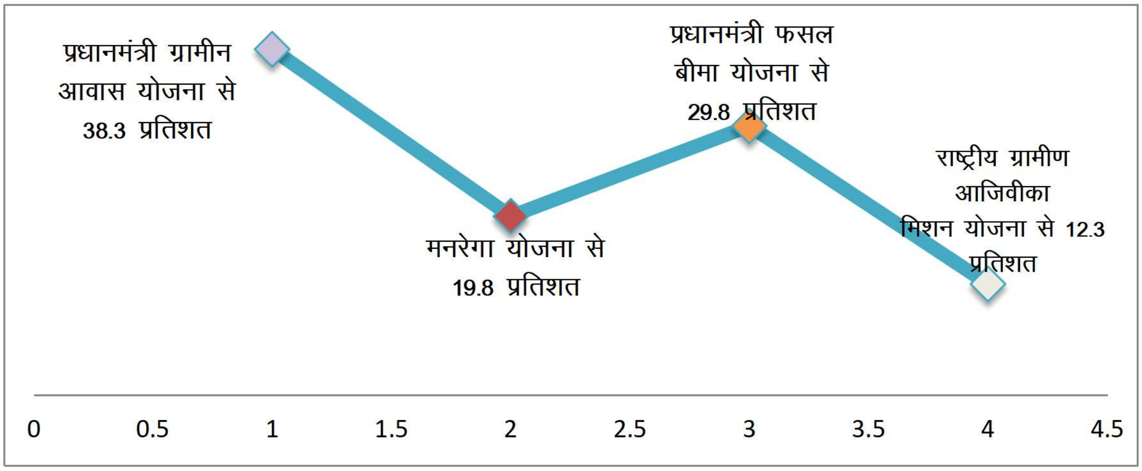

उपरोक्त तालिका में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली पिछड़ी जनजातीयों के परिवार के किसी सदस्य ने इन जनजातियों के विकास योजनाओं का लाभ लिया है यदि हाँ, तो किस योजना का लाभ मिला है के आधार पर वर्गीकृत कर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित ग्रामीण जनजातीयों में सर्वाधिक 38.3 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि सरकार द्वारा जनजातीयों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं में से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है जो कि सबसे

ज्यादा है। साथ ही 12.3 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि सरकार द्वारा जनजातीयों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं में से राष्ट्रीय ग्रामीण आजिवीका मिशन योजना का लाभ मिला है, जो कि सबसे कम है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय के परिवार के किसी सदस्य ने इन जनजातियों के विकास योजनाओं का लाभ लिया है यदि हाँ तो किसके माध्यम से पता चला के आधार पर विश्लेषण –: पिछड़ी जनजातीय समुदाय के परिवार के किसी सदस्य ने इन जनजातियों के विकास योजनाओं का लाभ लिया है यदि हाँ तो किसके माध्यम से पता चला के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें अग्र तालिका में दर्शाया गया है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय के परिवार के किसी सदस्य ने इन जनजातियों के विकास योजनाओं का लाभ लिया है यदि हाँ तो किसके माध्यम से पता चला के आधार पर वर्गीकरण

किसके माध्यम से पता चला	आवृति	प्रतिशत
मोबाईल एप	17	4.3
टी. वी.	74	18.5
रेडियो	163	40.8
fe= ,oa fj”rsnkjksa ls	126	31.5
lekpkj i=	20	5.
कुल	**400**	**100.0**

स्त्रोत :– स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

आरेख क्रमांक – पिछड़ी जनजातीय समुदाय के परिवार के किसी सदस्य ने इन जनजातियों के विकास योजनाओं का लाभ लिया है यदि हाँ तो किसके माध्यम से पता चला के आधार पर वर्गीकरण

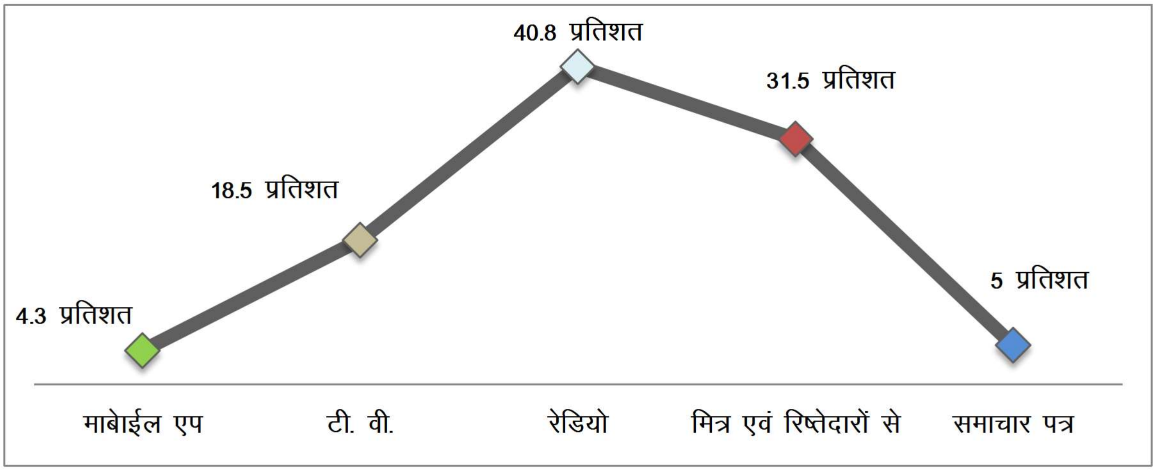

उपरोक्त तालिका में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली पिछड़ी जनजातीयों के यदि हाँ तो किसके माध्यम से पता चला के आधार पर वर्गीकृत कर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित ग्रामीण जनजातीयों में सर्वाधिक 40.8 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि सरकार द्वारा जनजातीयों के विकास के लिए चालाई गई विभिन्न योजनाओं कि जानकारी रेडियों के द्वारा प्राप्त की है, जो कि सबसे ज्यादा है। साथ ही 5 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि सरकार द्वारा जनजातीयों के विकास के लिए चालाई गई विभिन्न योजनाओं कि जानकारी समाचार–पत्र के द्वारा प्राप्त की है, जो कि सबसे कम है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में आर्थिक कठिनाईयों का समाना पड़ता है यदि हाँ तो किस प्रकार की आर्थिक कठिनाईयों का समाना पड़ता है के आधार पर विश्लेषण –: पिछड़ी जनजातीय समुदाय को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में आर्थिक कठिनाईयों का समाना पड़ता है यदि हाँ तो किस प्रकार की आर्थिक कठिनाईयों का समाना पड़ता है के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें अग्र तालिका में दर्शाया गया है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में आर्थिक कठिनाईयों का समाना पड़ता है यदि हाँ तो किस प्रकार की आर्थिक कठिनाईयों का समाना पड़ता है के आधार पर वर्गीकरण

प्रकार	आवृति	प्रतिशत

भोजन सम्बंधी	153	38.3
वस्त्र सम्बंधी	96	24
आवास सम्बंधी	75	18.8
अन्य	76	19
कुल	400	100.0

स्त्रोत :– स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

आरेख क्रमांक – पिछड़ी जनजातीय समुदाय को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में आर्थिक कठिनाईयों का समाना पड़ता है यदि हाँ तो किस प्रकार की आर्थिक कठिनाईयों का समाना पड़ता है के आधार पर वर्गीकरण

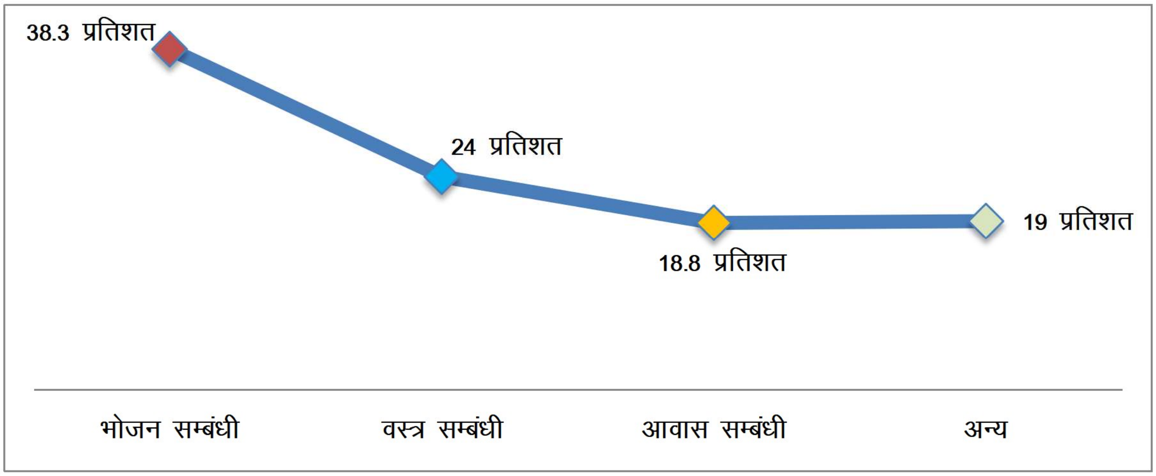

उपरोक्त तालिका में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली पिछड़ी जनजातीयों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में आर्थिक कठिनाईयों का समाना पड़ता है यदि हाँ तो किस प्रकार की आर्थिक कठिनाईयों का समाना पड़ता है के आधार पर वर्गीकृत कर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित ग्रामीण जनजातीयों में सर्वाधिक 38.3 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भोजन संबंधी आर्थिक कठिनाईयों का समाना करना पड़ा है, जो कि सबसे ज्यादा है।

साथ ही 18.8 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में आवास संबंध आर्थिक कठिनाईयों का समाना करना पड़ता है, जो कि सबसे कम है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजनाओं से लाभ मिलने से पूर्व आर्थिक स्थिति के आधार पर विश्लेषण –: पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजनाओं से लाभ मिलने से पूर्व आर्थिक स्थिति के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें अग्र तालिका में दर्शाया गया है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजनाओं से लाभ मिलने से पूर्व आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण

आर्थिक स्थिति	आवृति	प्रतिशत
उच्च	75	18.8
मध्यम	57	14.25
निम्न	181	45.25
अति निम्न	97	24.3
कुल	**400**	**100.0**

स्त्रोत :– स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समं

आरेख क्रमांक – पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजनाओं से लाभ मिलने से पूर्व आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण

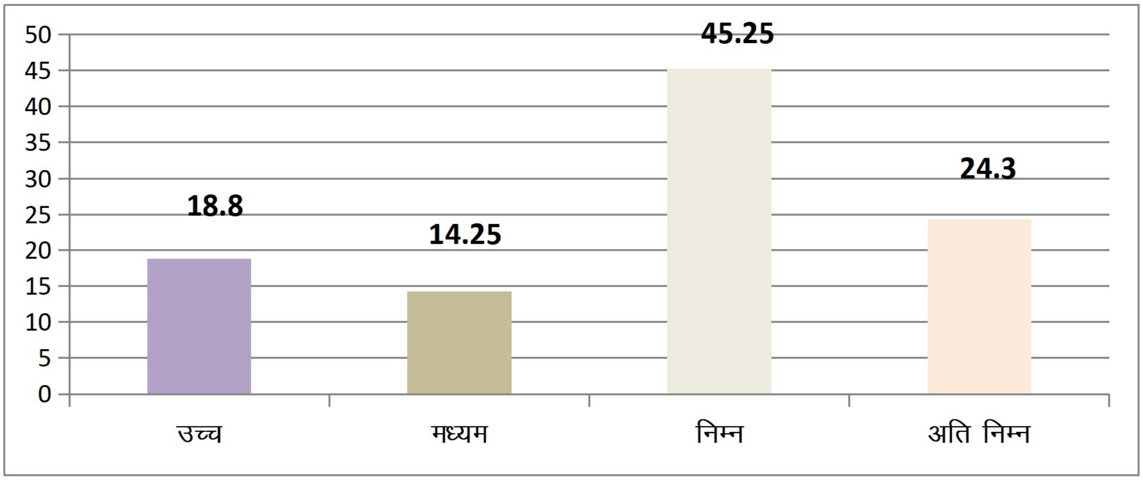

उपरोक्त तालिका में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली पिछड़ी जनजातीयों को शासकीय योजनाओं से लाभ मिलने से पूर्व आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत कर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित ग्रामीण जनजातीयों में सर्वाधिक 45.25 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि शासकीय योजनाओं से लाभ मिलने से पूर्व आर्थिक स्थिति निम्न थी, जो कि सबसे ज्यादा है। साथ ही 14.25 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि शासकीय योजनाओं से लाभ मिलने से पूर्व आर्थिक स्थिति मध्यम थी, जो कि सबसे कम है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजनाओं से लाभ मिलने के उपरान्त आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ हैं के आधार पर विश्लेषण –: पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजनाओं से लाभ मिलने के उपरान्त आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ हैं के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें अग्र तालिका में दर्शाया गया है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजनाओं से लाभ मिलने के उपरान्त आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ हैं के आधार पर वर्गीकरण

आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ हैं	आवृति	प्रतिशत
उच्च	64	16
मध्यम	225	56.25
अन्य	111	27.75

कुल	**400**	**100.0**

स्त्रोत :– स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

आरेख क्रमांक – पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजनाओं से लाभ मिलने के उपरान्त आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ हैं के आधार पर वर्गीकरण

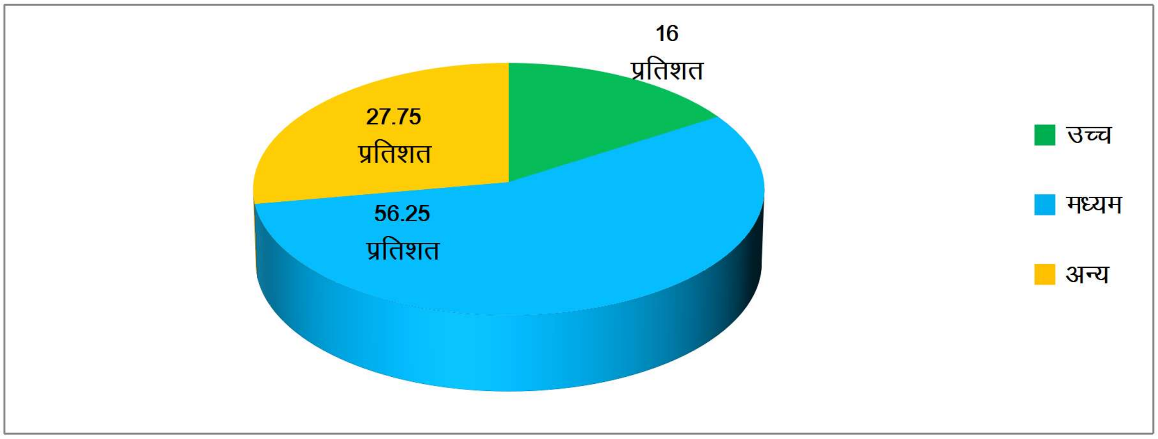

उपरोक्त तालिका में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली पिछड़ी जनजातीयों को शासकीय योजनाओं से लाभ मिलने के उपरान्त आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ हैं के आधार पर वर्गीकृत कर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित ग्रामीण जनजातीयों में सर्वाधिक 56.25 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि शासकीय योजनाओं से लाभ मिलने के उपरान्त आर्थिक स्थिति में मध्यम सुधार हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा है। साथ ही 16 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि शासकीय योजनाओं से लाभ मिलने के उपरान्त आर्थिक स्थिति में उच्च सुधार हुआ है जो कि सबसे कम है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजना से लाभ मिलने के पश्चात् आय के स्तर मे वृद्धि हो रही हैं के आधार पर विश्लेषण –: पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजना से लाभ मिलने के पश्चात् आय के स्तर मे वृद्धि हो रही हैं के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें अग्र तालिका में दर्शाया गया है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजना से लाभ मिलने के पश्चात् आय के स्तर मे वृद्धि हो रही हैं के आधार पर वर्गीकरण

शासकीय योजना से लाभ	आवृति	प्रतिशत
हां	271	67.75
नहीं	129	32.25
कुल	**400**	**100.0**

स्त्रोत :– स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

उपरोक्त तालिका में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली पिछड़ी जनजातीयों को शासकीय योजना से लाभ मिलने के पश्चात् आय के स्तर मे वृद्धि हो रही हैं के आधार पर वर्गीकृत कर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित ग्रामीण जनजातीयों में सर्वाधिक 67.75 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि शासकीय योजना से लाभ मिलने के पश्चात् आय के स्तर मे वृद्धि हो रही है, जो कि सबसे ज्यादा है। साथ ही 16 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि शासकीय योजना से लाभ मिलने के पश्चात् आय के स्तर मे वृद्धि नहीं हो रही है, जो कि सबसे कम है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजना से लाभ मिलने के पश्चात् आय के स्तर मे वृद्धि हो रही हैं यदि हाँ, तो शासकीय योजनाओं के फलस्वरूप आय में वृद्धि हुई है के आधार पर विश्लेषण –: पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजना से लाभ मिलने के पश्चात् आय के स्तर मे वृद्धि हो रही हैं यदि हाँ, तो शासकीय योजनाओं के फलस्वरूप आय में वृद्धि हुई है के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें अग्र तालिका में दर्शाया गया है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजना से लाभ मिलने के पश्चात् आय के स्तर मे वृद्धि हो रही हैं यदि हाँ, तो शासकीय योजनाओं के फलस्वरूप आय में वृद्धि हुई है के आधार पर वर्गीकरण

आय में वृद्धि	आवृति	प्रतिशत
1000 से 2000	37	9.3
2000 से 3000	68	17

3000 से 4000	97	24.3
4000 से 5000	96	24
5000 से अधिक	102	25.5
कुल	**400**	**100.0**

स्त्रोत :– स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

आरेख क्रमांक – पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजना से लाभ मिलने के पश्चात् आय के स्तर मे वृद्धि हो रही हैं यदि हाँ, तो शासकीय योजनाओं के फलस्वरूप आय में वृद्धि हुई है के आधार पर वर्गीकरण

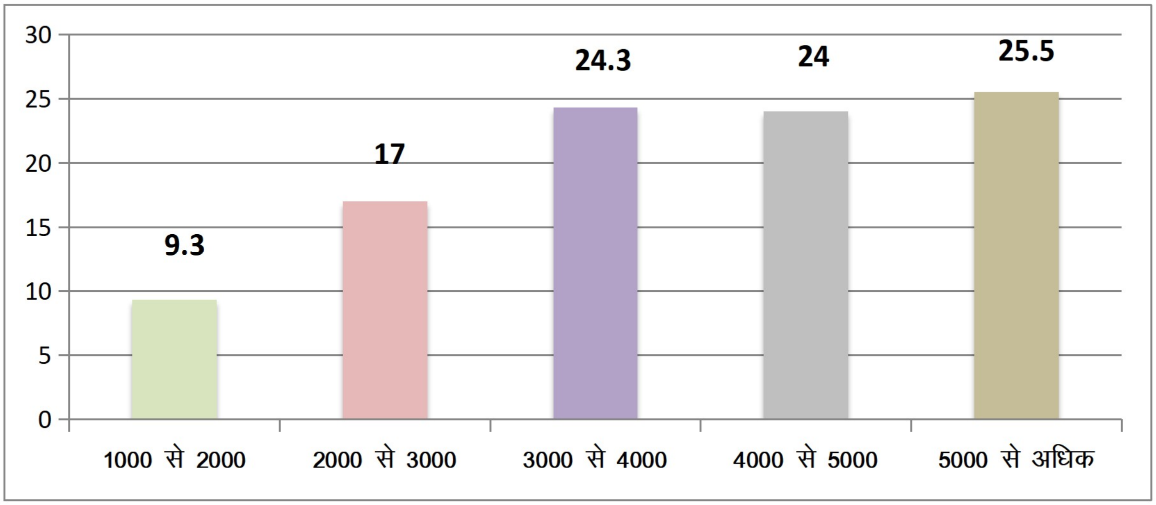

उपरोक्त तालिका में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली पिछड़ी जनजातीयों को शासकीय योजना से लाभ मिलने के पश्चात् आय के स्तर मे वृद्धि हो रही हैं यदि हाँ, तो शासकीय योजनाओं के फलस्वरूप आय में वृद्धि हुई है के आधार पर वर्गीकृत कर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित ग्रामीण जनजातीयों में सर्वाधिक 25.5 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि शासकीय योजनाओं के फलस्वरूप आय में 5000 से अधिक वृद्धि हुई है, जो कि सबसे ज्यादा है। साथ ही 19.3 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि शासकीय योजनाओं के फलस्वरूप आय में 1000 से 2000 तक वृद्धि हुई है, जो कि सबसे कम है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजना से लाभ मिलने के पश्चात् बच्चों को स्कूल की व स्वस्थ्य सुविधा देने में सक्षम हैं के आधार पर विश्लेषण –: पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजना से लाभ मिलने के पश्चात् बच्चों को स्कूल की व स्वस्थ्य सुविधा देने में सक्षम हैं के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें अग्र तालिका में दर्शाया गया है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजना से लाभ मिलने के पश्चात् बच्चों को स्कूल की व स्वस्थ्य सुविधा देने में सक्षम हैं के आधार पर वर्गीकरण

स्वस्थ्य सुविधा	आवृति	प्रतिशत
हां	261	65.25
नहीं	139	34.75
कुल	**400**	**100.0**

स्त्रोत :– स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

उपरोक्त तालिका में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली पिछड़ी जनजातीयों को शासकीय योजना से लाभ मिलने के पश्चात् बच्चों को स्कूल की व स्वस्थ्य सुविधा देने में सक्षम हैं के आधार पर वर्गीकृत कर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित ग्रामीण जनजातीयों में सर्वाधिक 65.25 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि शासकीय योजना से लाभ मिलने के पश्चात् बच्चों को स्कूल की व स्वस्थ्य सुविधा देने में सक्षम है, जो कि सबसे ज्यादा है। साथ ही 34.75 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि शासकीय योजना से लाभ मिलने के पश्चात् बच्चों को स्कूल की व स्वस्थ्य सुविधा देने में सक्षम नहीं है, जो कि सबसे कम है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजना से लाभ मिलने के पश्चात् भौतिक सुख–सुविधा में वृद्धि हो रही हैं के आधार पर विश्लेषण –: पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजना से लाभ मिलने के पश्चात् भौतिक सुख–सुविधा में वृद्धि हो रही हैं के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें अग्र तालिका में दर्शाया गया है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजना से लाभ मिलने के पश्चात् भौतिक सुख–सुविधा में वृद्धि हो रही हैं के आधार पर वर्गीकरण

भौतिक सुख–सुविधा	आवृति	प्रतिशत
हां	291	52.25
नहीं	109	27.25
कुल	**400**	**100.0**

स्त्रोत :– स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

उपरोक्त तालिका में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली पिछड़ी जनजातीयों को शासकीय योजना से लाभ मिलने के पश्चात् भौतिक सुख–सुविधा में वृद्धि हो रही हैं के आधार पर वर्गीकृत कर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित ग्रामीण जनजातीयों में सर्वाधिक 52.25 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि शासकीय योजना से लाभ मिलने के पश्चात् भौतिक सुख–सुविधा में वृद्धि हो रही है, जो कि सबसे ज्यादा है। साथ ही 27.25 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि शासकीय योजना से लाभ मिलने के पश्चात् भौतिक सुख–सुविधा में वृद्धि नहीं हो रही है, जो कि सबसे कम है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजनाओं के फलस्वरूप घर में बिजली, पानी व शोचालय की सुविधाओं में वृद्धि हुई के आधार पर विश्लेषण –: पिछड़ी

जनजातीय समुदाय को शासकीय योजनाओं के फलस्वरूप घर में बिजली, पानी व शोचालय की सुविधाओं में वृद्धि हुई के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें अग्र तालिका में दर्शाया गया है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजनाओं के फलस्वरूप घर में बिजली, पानी व शोचालय की सुविधाओं में वृद्धि हुई हैं के आधार पर वर्गीकरण

शोचालय की सुविधा	आवृति	प्रतिशत
हां	241	60.25
नहीं	159	39.75
कुल	**400**	**100.0**

स्त्रोत :– स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

उपरोक्त तालिका में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली पिछड़ी जनजातीयों को शासकीय योजनाओं के फलस्वरूप घर में बिजली, पानी व शोचालय की सुविधाओं में वृद्धि हुई हैं के आधार पर वर्गीकृत कर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित ग्रामीण जनजातीयों में सर्वाधिक 60.25 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि शासकीय योजनाओं के फलस्वरूप घर में बिजली, पानी व शोचालय की सुविधाओं में वृद्धि हुई है, जो कि सबसे ज्यादा है। साथ ही 39.75 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि शासकीय योजनाओं के फलस्वरूप घर में बिजली, पानी व शोचालय की सुविधाओं में वृद्धि नहीं हुई है, जो कि सबसे कम है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजनाओं के संचालत के पश्चात् रोजगार में वृद्धि हुई हैं के आधार पर विश्लेषण –: पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजनाओं के संचालत के पश्चात् रोजगार में वृद्धि हुई हैं के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें अग्र तालिका में दर्शाया गया है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजनाओं के संचालत के पश्चात् रोजगार में वृद्धि हुई हैं के आधार पर वर्गीकरण

रोजगार में वृद्धि	आवृति	प्रतिशत
हां	231	57.75
नहीं	169	42.25
कुल	**400**	**100.0**

स्त्रोत :– स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

उपरोक्त तालिका में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली पिछड़ी जनजातीयों को शासकीय योजनाओं के संचालत के पश्चात् रोजगार में वृद्धि हुई हैं के आधार पर वर्गीकृत कर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित ग्रामीण जनजातीयों में सर्वाधिक 57.75 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि शासकीय योजनाओं के संचालत के पश्चात् रोजगार में वृद्धि हुई है, जो कि सबसे ज्यादा है। साथ ही 39.75 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि शासकीय योजनाओं के संचालत के पश्चात् रोजगार में वृद्धि नहीं हुई है, जो कि सबसे कम है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजनाओं के फलस्वरूप पूरे वर्ष रोजगार मिल रहा है के आधार पर विश्लेषण –: पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजनाओं के फलस्वरूप पूरे वर्ष रोजगार मिल रहा है के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें अग्र तालिका में दर्शाया गया है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजनाओं के फलस्वरूप पूरे वर्ष रोजगार मिल रहा है के आधार पर वर्गीकरण

वर्ष रोजगार मिल रहा है	आवृति	प्रतिशत
हां	197	49.25
नहीं	203	50.75
कुल	**400**	**100.0**

स्त्रोत :– स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

उपरोक्त तालिका में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली पिछड़ी जनजातीयों को शासकीय योजनाओं के फलस्वरूप पूरे वर्ष रोजगार मिल रहा है के आधार पर वर्गीकृत कर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित ग्रामीण जनजातीयों में सर्वाधिक 50.25 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि शासकीय योजनाओं के फलस्वरूप पूरे वर्ष रोजगार नहीं मिल रहा है, जो कि सबसे ज्यादा है। साथ ही 47.75 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि शासकीय योजनाओं के फलस्वरूप पूरे वर्ष रोजगार नहीं मिल रहा है, जो कि सबसे कम है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय को रोजगारी मिलने के बाद शाहरों की ओर पलायन करते हैं के आधार पर विश्लेषण –: पिछड़ी जनजातीय समुदाय को रोजगारी मिलने के बाद शाहरों की ओर पलायन करते हैं के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें अग्र तालिका में दर्शाया गया है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय को रोजगारी मिलने के बाद शाहरों की ओर पलायन करते हैं के आधार पर वर्गीकरण

शाहरों की ओर पलायन	आवृति	प्रतिशत
हां	127	31.75
नहीं	273	31.75
कुल	**400**	**100.0**

स्त्रोत :– स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

उपरोक्त तालिका में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली पिछड़ी जनजातीयों को रोजगारी मिलने के बाद शाहरों की ओर पलायन करते है के आधार पर वर्गीकृत कर

विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित ग्रामीण जनजातीयों में सर्वाधिक 68.25 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि रोजगारी मिलने के बाद शाहरों की ओर पलायन नहीं करते है, जो कि सबसे ज्यादा है। साथ ही 31.75 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि रोजगारी मिलने के बाद शाहरों की ओर पलायन करते है, जो कि सबसे कम है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय को आर्थिक स्तर में सुधार होने से क्या आप बचत कर पाते हैं के आधार पर वर्गीकरण

बचत कर पाते	आवृति	प्रतिशत
हां	287	77.7
नहीं	113	28.25
कुल	**400**	**100.0**

स्त्रोत :– स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

उपरोक्त तालिका में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली पिछड़ी जनजातीयों की आर्थिक स्तर में सुधार होने से क्या आप बचत कर पाते हैं के आधार पर वर्गीकृत कर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित ग्रामीण जनजातीयों में सर्वाधिक 77.7 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि आर्थिक स्तर में सुधार होने से बचत कर पाते है, जो कि सबसे ज्यादा है। साथ ही 28.25 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि आर्थिक स्तर में सुधार होने से नहीं बचत कर पाते है, जो कि सबसे कम है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजना से लाभ मिलने के बाद सामाजिक स्तर में परिवर्तन आया है के आधार पर विश्लेषण –: पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजना से लाभ मिलने के बाद सामाजिक स्तर में परिवर्तन आया है के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें अग्र तालिका में दर्शाया गया है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजना से लाभ मिलने के बाद सामाजिक स्तर में परिवर्तन आया है के आधार पर वर्गीकरण

सामाजिक स्तर में परिवर्तन	आवृति	प्रतिशत
हां	201	51.25
नहीं	199	49.75
कुल	**400**	**100.0**

स्त्रोत :– स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

उपरोक्त तालिका में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली पिछड़ी जनजातीयों को शासकीय योजना से लाभ मिलने के बाद क्या आपके सामाजिक स्तर में परिवर्तन आया है के आधार पर वर्गीकृत कर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित ग्रामीण जनजातीयों में सर्वाधिक 51.25 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि शासकीय योजना से लाभ मिलने के बाद क्या आपके सामाजिक स्तर में परिवर्तन आया है, जो कि सबसे ज्यादा है। साथ ही 49.75 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि शासकीय योजना से लाभ मिलने के बाद क्या आपके सामाजिक स्तर में परिवर्तन नहीं आया है, जो कि सबसे कम है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय के विकास के लिए संचालित शासकीय योजनाओं के फलस्वरूप जीवन किसी प्रकार का परिवर्तन आया है के आधार पर विश्लेषण –:

पिछड़ी जनजातीय समुदाय के विकास के लिए संचालित शासकीय योजनाओं के फलस्वरूप जीवन किसी प्रकार का परिवर्तन आया है के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें अग्र तालिका में दर्शाया गया है।

जनजातिय विकास के लिए संचालित शासकीय योजनाओं के फलस्वरूप जीवन किसी प्रकार का परिवर्तन आया है के आधार पर वर्गीकरण

जनजातिय विकास	आवृति	प्रतिशत
हां	211	52.75
नहीं	189	47.25
कुल	**400**	**100.0**

स्त्रोत :– स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

उपरोक्त तालिका में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली पिछड़ी जनजातिय विकास के लिए संचालित शासकीय योजनाओं के फलस्वरूप आपके जीवन किसी प्रकार का परिवर्तन आया है के आधार पर वर्गीकृत कर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित ग्रामीण जनजातीयों में सर्वाधिक 52.75 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि जनजातिय विकास के लिए संचालित शासकीय योजनाओं के फलस्वरूप आपके जीवन किसी प्रकार का परिवर्तन आया है, जो कि सबसे ज्यादा है। साथ ही 47.25 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि जनजातिय विकास के लिए संचालित शासकीय योजनाओं के फलस्वरूप आपके जीवन किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है, जो कि सबसे कम है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजना से लाभ मिलने के पूर्व आप विभिन्न प्रकार के व्ययों की पूर्ति हेतु आर्थिक व्यवस्था कहाँ से करते थे के आधार पर विश्लेषण –: पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजना से लाभ मिलने के पूर्व आप विभिन्न प्रकार के व्ययों की पूर्ति हेतु आर्थिक व्यवस्था कहाँ से करते थे के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें अग्र तालिका में दर्शाया गया है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजना से लाभ मिलने के पूर्व आप विभिन्न प्रकार के व्ययों की पूर्ति हेतु आर्थिक व्यवस्था कहाँ से करते थे के आधार पर वर्गीकरण

आर्थिक व्यवस्था	आवृति	प्रतिशत
स्वयं की बचत	154	38.5
साहूकार से ब्याज पर	183	45.8
पड़ोसी से उधार	63	15.8
कुल	**400**	**100.0**

स्त्रोत :– स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

आरेख क्रमांक – पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शा. योजना से लाभ मिलने के पूर्व आप विभिन्न प्रकार के व्ययों की पूर्ति हेतु आर्थिक व्यवस्था कहाँ से करते थे के आधार पर वर्गीकरण

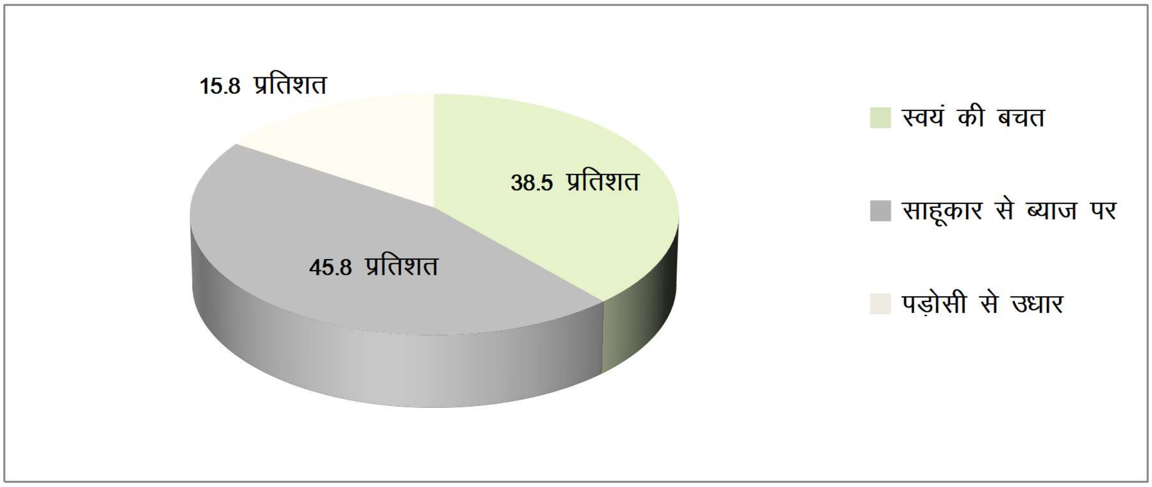

उपरोक्त तालिका में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली पिछडी़ जनजातीयों को शासकीय योजना से लाभ मिलने के पूर्व विभिन्न प्रकार के व्ययों की पूर्ति हेतु आर्थिक व्यवस्था कहाँ से करते थे के आधार पर वर्गीकृत कर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित ग्रामीण जनजातीयों में सर्वाधिक 45.8 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि शासकीय योजना से लाभ मिलने के पूर्व विभिन्न प्रकार के व्ययों की पूर्ति हेतु आर्थिक व्यवस्था साहूकार से ब्याज पर ऋण लेकर करते थे, जो कि सबसे ज्यादा है। साथ ही 15.8 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि

शासकीय योजना से लाभ मिलने के पूर्व विभिन्न प्रकार के व्ययों की पूर्ति हेतु आर्थिक व्यवस्था पड़ोसी से उधर लेकर करते थे, जो कि सबसे कम है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजना से लाभ प्राप्त करने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा हैं के आधार पर विश्लेषण –: पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजना से लाभ प्राप्त करने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा हैं के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें अग्र तालिका में दर्शाया गया है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजना से लाभ प्राप्त करने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा हैं के आधार पर वर्गीकरण

कठिनाई	आवृति	प्रतिशत
हां	155	38.75
नहीं	245	61.25
कुल	**400**	**100.0**

स्त्रोत :– स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

उपरोक्त तालिका में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली पिछड़ी जनजातीयों को शासकीय योजना से लाभ प्राप्त करने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा है के आधार पर वर्गीकृत कर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित ग्रामीण जनजातीयों में सर्वाधिक 61.25 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि शासकीय योजना से लाभ प्राप्त करने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है, जो कि सबसे ज्यादा है। साथ ही 38.75 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि शासकीय योजना से लाभ प्राप्त करने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा है, जो कि सबसे कम है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय के विकास के लिए संचालित शासकीय योजनायें आपके लिए आवश्यक है के आधार पर विश्लेषण –: पिछड़ी जनजातीय समुदाय के विकास

के लिए संचालित शासकीय योजनायें आपके लिए आवश्यक है के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें अग्र तालिका में दर्शाया गया है।

जनजातिय समुदाय के विकास के लिए संचालित शासकीय योजनायें आपके लिए आवश्यक है के आधार पर वर्गीकरण

जनजातिय समुदाय का विकास	आवृति	प्रतिशत
हां	311	77.7
नहीं	89	22.30
कुल	**400**	**100.0**

स्त्रोत :– स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

उपरोक्त तालिका में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली पिछड़ी जनजातीय समुदाय के विकास के लिए संचालित शासकीय योजनायें आपके लिए आवश्यक है के आधार पर वर्गीकृत कर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित ग्रामीण जनजातीयों में सर्वाधिक 77.7 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि जनजातीय समुदाय के विकास के लिए संचालित शासकीय योजनायें आवश्यक है, जो कि सबसे ज्यादा है। साथ ही 22.30 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि जनजातीय समुदाय के विकास के लिए संचालित शासकीय योजनायें आवश्यक नहीं है, जो कि सबसे कम है।

पिछड़ी जनजातिय समुदाय को शासकीय योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त हुआ के आधार पर विश्लेषण –: पिछड़ी जनजातिय समुदाय को शासकीय योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त हुआ के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए है, उन्हें अग्र तालिका में दर्शाया गया है।

पिछड़ी जनजातिय समुदाय को शासकीय योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त हुआ के आधार पर वर्गीकरण

योजनाओं का लाभ	आवृति	प्रतिशत
सरलता से	96	24

रूपये खर्च करके	77	19.3
राजनैतिक दबाव से	164	41
अन्य	63	15.8
कुल	**400**	**100.0**

स्त्रोत :– स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

आरेख क्रमांक – पिछड़ी जनजातीय समुदाय को शासकीय योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त हुआ के आधार पर वर्गीकरण

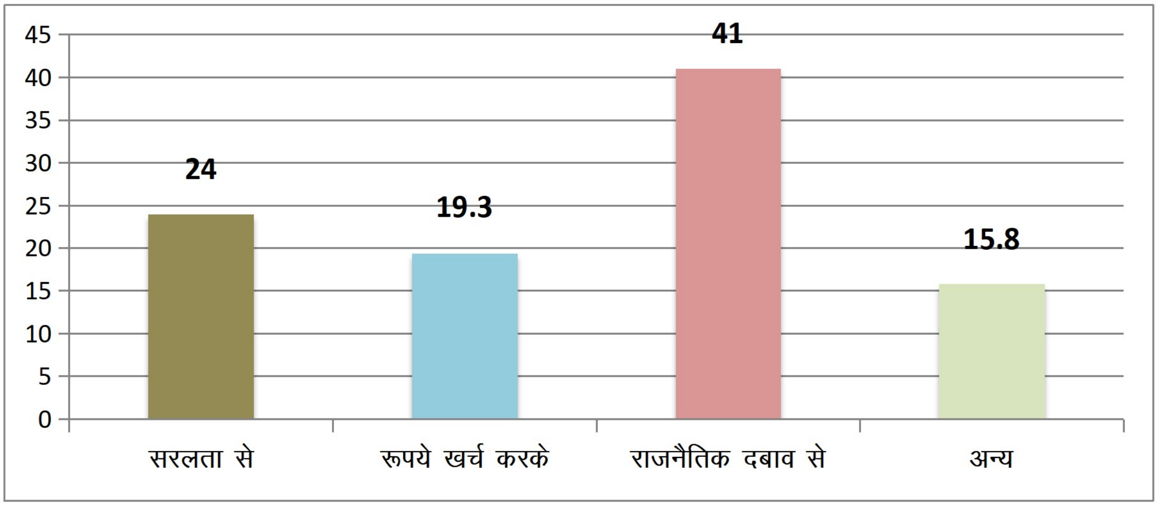

उपरोक्त तालिका में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली पिछड़ी जनजातीयों को शासकीय योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त हुआ के आधार पर वर्गीकृत कर विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित ग्रामीण जनजातीयों में सर्वाधिक 41 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि शासकीय योजनाओं का लाभ राजनैतिक दबाव से प्राप्त हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा है। साथ ही 15.8 प्रतिशत जनजातीयों का कहना है कि शासकीय योजनाओं का लाभ अन्य कारणों से प्राप्त हुआ है, जो कि सबसे कम है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय की शिक्षा का स्तर एवं शासकीय योजना से लाभ मिलने के पश्चात् आय में वृद्धि के मध्य अन्तर संबंध की स्थिति :– अग्र तालिका में पिछड़ी

जनजातीय समुदाय की शिक्षा का स्तर एवं शासकीय योजना से लाभ मिलने के पश्चात् आय में वृद्धि के मध्य अन्तर संबंध को विश्लेषित किया गया है।

शिक्षा का स्तर	आय में वृद्धि					कुल
	1000 से 2000	2000 से 3000	3000 से 4000	4000 से 5000	5000 से अधिक	
प्राथमिक	4 (1)	69 (17.25)	5 (1.25)	0 (0)	0 (0)	78 (19.5)
माध्यमिक	13 (3.25)	0 (0)	96 (24)	15 (3.75)	0 (0)	124 (31)
हाईस्कूल	0 (0)	0 (0)	1 (0.25)	69 (17.25)	0 (0)	70 (17.5)
हाई सैकेण्डरी	0 (0)	0 (0)	43 (10.75)	15 (3.75)	7 (1.75)	65 (16.25)
हाई सैकेण्डरी से अधिक	0 (0)	5 (1.25)	18 (4.5)	27 (6.75)	13 (3.25)	63 (15.75)
कुल	**17** **(4.25)**	**74** **(18.5)**	**163** **(40.75)**	**126** **(31.5)**	**20** **(5)**	**400** **(100)**

स्त्रोतः– स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

उपरोक्त तालिका में आदिवासी समाज में मानवता का अध्ययन हेतु पिछड़ी जनजातीय समुदाय की शिक्षा का स्तर एवं शासकीय योजना से लाभ मिलने के पश्चात् आय में वृद्धि के मध्य अन्तर संबंध की संरचना की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण उत्तरदाताओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में समावेशी विकास का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का ग्रामीण उत्तरदाताओं में सर्वाधिक 24 प्रतिशत है जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, एवं इन उत्तरदाताओं ने माध्यमिक तक शिक्षा प्राप्त की है, जिनकी वार्षिक आय में 3000 से 4000 हजार तक

वृद्धि हुई है जो कि सबसे ज्यादा है। तथा 17.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है तथा इन उत्तरदाताओं की वार्षिक आय में 2000 से 3000 हजार तक वृद्धि हुई है। तथा 6.75 प्रतिशत ऐसे उत्तरदाता है जिन्होंने हाई सैकेण्डरी से अधिक शिक्षा प्राप्त की है एवं इन उत्तरदाताओं की वार्षिक आय में 4000 से 5000 हजार तक वृद्धि हुई है। और 1.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हाई सैकेण्डरी तक शिक्षा प्राप्त की है तथा इन उत्तरदाताओं की वार्षिक आय 5000 हजार से अधिक वृद्धि हुई है जो कि सबसे कम है। अतः स्पष्ट है कि 24 प्रतिशत है जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, एवं इन उत्तरदाताओं ने माध्यमिक तक शिक्षा प्राप्त की है, जिनकी वार्षिक आय में 3000 से 4000 हजार तक वृद्धि हुई है जो कि सबसे ज्यादा है। तथा 1.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हाई सैकेण्डरी तक शिक्षा प्राप्त की है तथा इन उत्तरदाताओं की वार्षिक आय 5000 हजार से अधिक वृद्धि हुई है जो कि सबसे कम है।

उपरोक्त तालिका के पश्चात् पिछड़ी जनजातीय समुदाय की शिक्षा का स्तर एवं शासकीय योजना से लाभ मिलने के पश्चात् आय में वृद्धि के मध्य अन्तर संबंध की संरचना की स्थिति के मध्य स्वतंत्रता का परीक्षण करने के लिए काई वर्ग परीक्षण किया गया है, जिसके अन्तर्गत शून्य परिकल्पना निम्नलिखित है। पिछड़ी जनजातीय समुदाय की शिक्षा का स्तर एवं शासकीय योजना से लाभ मिलने के पश्चात् आय में वृद्धि के मध्य अन्तर संबंध की संरचना की स्थिति के मध्य कोई सार्थक संबंध है। इस परिकल्पना के परीक्षण के लिए तालिका में दर्शाए गए आंकडों के अनुसार काई वर्ग परीक्षण करके जो परिणाम प्राप्त हुए है, उन्हें तालिका में दर्शाया गया है। काई वर्ग परीक्षण में पिछड़ी जनजातीय समुदाय की शिक्षा का स्तर एवं शासकीय योजना से लाभ मिलने के पश्चात् आय में वृद्धि के मध्य अन्तर संबंध की संरचना की स्थिति :–

काई वर्ग परीक्षण			
	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
पियर्सन काई वर्ग	72.743^{a}	16	.000

संभावना अनुपात परिक्षण	42.977	16	.000
लीनियर बाय लीनियर एसोसिएशन	47.031	1	.000
N of Valid Cases	400		
a. 8 cells (32.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.68.			

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण के पश्चात् स्पष्ट होता है कि 0.05 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर पिछड़ी जनजातीय समुदाय की शिक्षा का स्तर एवं शासकीय योजना से लाभ मिलने के पश्चात् आय में वृद्धि के मध्य अन्तर संबंध की संरचना की स्थिति के मध्य कोई सार्थक संबंध नहीं है इसलिए शून्य परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पिछड़ी जनजातीय समुदाय की शिक्षा का स्तर एवं शासकीय योजना से लाभ मिलने के पश्चात् आय में वृद्धि के मध्य सार्थक संबंध है, जिसके कारण ग्रामीण उत्तरदाताओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में शासकीय योजनाओं के प्रभाव में सर्वाधिक ग्रामीण उत्तरदाताओं की संख्या 24 प्रतिशत है जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, एवं इन उत्तरदाताओं ने माध्यमिक तक शिक्षा प्राप्त की है, जिनकी वार्षिक आय में 3000 से 4000 हजार तक वृद्धि हुई है जो कि सबसे ज्यादा है। तथा 1.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हाई सैकेण्डरी तक शिक्षा प्राप्त की है तथा इन उत्तरदाताओं की वार्षिक आय 5000 हजार से अधिक वृद्धि हुई है जो कि सबसे कम है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय की शिक्षा का स्तर एवं शा. योजनाओं से लाभ प्राप्ति के पश्चात् आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के मध्य अन्तर संबंध की स्थिति :– अग्र तालिका में पिछड़ी जनजातीय समुदाय की शिक्षा का स्तर एवं शा. योजनाओं से लाभ प्राप्ति के पश्चात् आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के मध्य अन्तर संबंध को विश्लेषित किया गया है।

शिक्षा का स्तर	शा. योजनाओं से लाभ प्राप्ति के पश्चात् आर्थिक स्थिति में परिवर्तन				कुल
	रोजगार के स्तर में वृद्धि	आय के स्तर में सुधार	आवास के स्वरूप में परिवर्तन	कोई परिवर्तन नहीं	
प्राथमिक	8 (2)	70 (17.5)	0 (0)	0 (0)	78 (19.5)
माध्यमिक	6 (1.5)	23 (5.75)	95 (23.75)	0 (0)	124 (31)
हाईस्कूल	0 (0)	1 (0.25)	40 (10)	29 (7.25)	70 (17.5)
हाई सैकेण्डरी	0 (0)	17 (4.25)	18 (4.5)	30 (7.5)	65 (16.25)
हाई सैकेण्डरी से अधिक	0 (0)	23 (5.75)	27 (6.75)	13 (3.25)	63 (15.75)
कुल	**14** **(3.5)**	**134** **(33.5)**	**180** **(45)**	**72** **(18)**	**400** **(100)**

स्त्रोतः– स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

उपरोक्त तालिका में आदिवासी समाज में मानवता का अध्ययन हेतु शिक्षा का स्तर एवं शा. योजनाओं से लाभ प्राप्ति के पश्चात् आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के मध्य अन्तर संबंध की संरचना की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण उत्तरदाताओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में शासकीय योजनाओं का ग्रामीण उत्तरदाताओं में सर्वाधिक 23.75 प्रतिशत है जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, एवं इन उत्तरदाताओं ने माध्यमिक तक शिक्षा प्राप्त कि है, एवं इन उत्तरदाताओं का कहना है कि शा. योजनाओं से लाभ प्राप्ति के पश्चात् आवास के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा है। तथा 17.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं

ने प्राथमिक तक शिक्षा प्राप्त कि है एवं इन उत्तरदाताओं का कहना है कि शा. योजनाओं से लाभ प्राप्ति के पश्चात् आय के स्तर में सुधार हुआ है। तथा 7.5 प्रतिशत ऐसे उत्तरदाता है जिन्होंने हाई सैण्केड़री तक शिक्षा प्राप्त की है जिनका कहना है शा. योजनाओं से लाभ प्राप्ति के पश्चात् कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जो कि सबसे कम है। अतः स्पष्ट है कि 23.75 प्रतिशत है जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, एवं इन उत्तरदाताओं ने माध्यमिक तक शिक्षा प्राप्त कि है, एवं इन उत्तरदाताओं का कहना है कि शा. योजनाओं से लाभ प्राप्ति के पश्चात् आवास के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा है। तथा 7.5 प्रतिशत ऐसे उत्तरदाता है जिन्होंने हाई सैण्केड़री तक शिक्षा प्राप्त की है जिनका कहना है शा. योजनाओं से लाभ प्राप्ति के पश्चात् कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जो कि सबसे कम है।

उपरोक्त तालिका के पश्चात् शिक्षा का स्तर एवं शा. योजनाओं से लाभ प्राप्ति के पश्चात् आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के मध्य अन्तर संबंध की संरचना की स्थिति के मध्य स्वतंत्रता का परीक्षण करने के लिए सह–संबंध परीक्षण किया गया है, जिसके अन्तर्गत शून्य परिकल्पना निम्नलिखित है। शिक्षा का स्तर एवं शा. योजनाओं से लाभ प्राप्ति के पश्चात् आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के मध्य अन्तर संबंध की संरचना की स्थिति के मध्य कोई सार्थक संबंध है। इस परिकल्पना के परीक्षण के लिए तालिका में दर्शाए गए आंकडों के अनुसार सह–संबंध परीक्षण करके जो परिणाम प्राप्त हुए है, उन्हें तालिका में दर्शाया गया है। सह–संबंध परीक्षण में शिक्षा का स्तर एवं शा. योजनाओं से लाभ प्राप्ति के पश्चात् आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के मध्य अन्तर संबंध की संरचना की स्थिति :–

सह–संबंध का परीक्षण

		Value	Asymp. Std. Error[a]	Approx. T[b]	Approx. Sig.
Interval by Interval	Pearson”s R	.427	.041	9.434	.000[c]
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	.472	.046	10.670	.000[c]

N of Valid Cases	400			
a. Not assuming the null hypothesis.				
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.				
c. Based on normal approximation.				

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण के पश्चात् स्पष्ट होता है कि 0.05 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर शिक्षा का स्तर एवं शा. योजनाओं से लाभ प्राप्ति के पश्चात् आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के मध्य अन्तर संबंध की संरचना की स्थिति के मध्य कोई सार्थक संबंध नहीं है इसलिए शून्य परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शिक्षा का स्तर एवं शा. योजनाओं से लाभ प्राप्ति के पश्चात् आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के मध्य सार्थक संबंध है, जिसके कारण ग्रामीण उत्तरदाताओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में शासकीय योजनाओं के प्रभाव में सर्वाधिक ग्रामीण उत्तरदाताओं की संख्या 23.75 प्रतिशत है जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, एवं इन उत्तरदाताओं ने माध्यमिक तक शिक्षा प्राप्त कि है, एवं इन उत्तरदाताओं का कहना है कि शा. योजनाओं से लाभ प्राप्ति के पश्चात् आवास के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा है। तथा 7.5 प्रतिशत ऐसे उत्तरदाता है जिन्होंने हाई सैण्केड़री तक शिक्षा प्राप्त की है जिनका कहना है शा. योजनाओं से लाभ प्राप्ति के पश्चात् कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जो कि सबसे कम है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय की शिक्षा का स्तर एवं शा. योजनाओं से लाभ प्राप्ति के पश्चात् जीवन स्तर में सामाजिक परिवर्तन के मध्य अन्तर संबंध की स्थिति :– अग्र तालिका में पिछड़ी जनजातीय समुदाय की शिक्षा का स्तर एवं शा. योजनाओं से लाभ

प्राप्ति के पश्चात् जीवन स्तर में सामाजिक परिवर्तन के मध्य अन्तर संबंध को विश्लेषित किया गया है।

शिक्षा का स्तर	शा. योजनाओं से लाभ प्राप्ति के पश्चात् जीवन स्तर में सामाजिक परिवर्तन				कुल
	रहन–सहन का उच्च स्तर	बच्चों की शिक्षा का उच्च स्तर	सामान्य जीवन स्तर	कोई परिवर्तन नहीं	
प्राथमिक	78 (10.5)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	78 (19.5)
माध्यमिक	33 (8.25)	91 (22.75)	0 (0)	0 (0)	124 (31)
हाईस्कूल	1 (0.25)	38 (9.5)	31 (7.75)	0 (0)	70 (17.5)
हाई सैकेण्डरी	43 (10.75)	0 (0)	19 (4.75)	3 (0.75)	65 (16.25)
हाई सैकेण्डरी से अधिक	23 (5.75)	27 (6.75)	0 (0)	13 (3.25)	63 (15.75)
कुल	**178** **(44.5)**	**156** **(39)**	**50** **(12.5)**	**16** **(4)**	**400** **(100)**

स्त्रोतः– स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

उपरोक्त तालिका में आदिवासी समाज में मानवता का अध्ययन हेतु शिक्षा का स्तर एवं शा. योजनाओं से लाभ प्राप्ति के पश्चात् जीवन स्तर में सामाजिक परिवर्तन के मध्य अन्तर संबंध की संरचना की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण उत्तरदाताओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में शासकीय योजनाओं के प्रभाव में ग्रामीण उत्तरदाताओं में सर्वाधिक 22.75 प्रतिशत है जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, एवं इन उत्तरदाताओं ने माध्यमिक तक शिक्षा प्राप्त की

है, एवं इन उत्तरदाताओं का कहना है कि शा. योजनाओं से लाभ प्राप्ति के पश्चात् बच्चों की शिक्षा में परिवर्तन हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा है। तथा 10.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्राथमिक तक शिक्षा प्राप्त की है तथा इन उत्तरदाताओं का कहना है कि शा. योजनाओं से लाभ प्राप्ति के पश्चात् रहन–सहन में परिवर्तन हुआ है। तथा 7.75 प्रतिशत ऐसे उत्तरदाता है जिन्होंने हाईस्कूल तक शिक्षा प्राप्त की है एवं इन उत्तरदाताओं का कहना है कि शा. योजनाओं से लाभ प्राप्ति के पश्चात् सामान्य जीवन स्तर में परिवर्तन हुआ है जो कि सबसे कम है। साथ ही 3.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हाई सैकेण्डरी से अधिक शिक्षा प्राप्त की है और इन उत्तरदाताओं का कहना है कि शा. योजनाओं से लाभ प्राप्ति के पश्चात् सामान्य जीवन स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जो कि सबसे कम है। अतः स्पष्ट है कि 22.75 प्रतिशत है जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, एवं इन उत्तरदाताओं ने माध्यमिक तक शिक्षा प्राप्त की है, एवं इन उत्तरदाताओं का कहना है कि शा. योजनाओं से लाभ प्राप्ति के पश्चात् बच्चों की शिक्षा में परिवर्तन हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा है। तथा 3.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हाई सैकेण्डरी से अधिक शिक्षा प्राप्त की है और इन उत्तरदाताओं का कहना है कि शा. योजनाओं से लाभ प्राप्ति के पश्चात् सामान्य जीवन स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जो कि सबसे कम है।

उपरोक्त तालिका के पश्चात् शिक्षा का स्तर एवं शा. योजनाओं से लाभ प्राप्ति के पश्चात् जीवन स्तर में सामाजिक परिवर्तन के मध्य अन्तर संबंध की संरचना की स्थिति के मध्य स्वतंत्रता का परीक्षण करने के लिए काई वर्ग परीक्षण किया गया है, जिसके अन्तर्गत शून्य परिकल्पना निम्नलिखित है। शिक्षा का स्तर एवं शा. योजनाओं से लाभ प्राप्ति के पश्चात् जीवन स्तर में सामाजिक परिवर्तन के मध्य अन्तर संबंध की संरचना की स्थिति के मध्य कोई सार्थक संबंध है। इस परिकल्पना के परीक्षण के लिए तालिका में दर्शाए गए आंकडों के अनुसार काई वर्ग परीक्षण करके जो परिणाम प्राप्त हुए है, उन्हें तालिका में दर्शाया गया है। काई वर्ग परीक्षण में ग्रामीण उत्तरदाताओं की शिक्षा का स्तर एवं शा. योजनाओं से लाभ प्राप्ति के पश्चात् जीवन स्तर में सामाजिक परिवर्तन के मध्य अन्तर संबंध की संरचना की स्थिति :–

काई वर्ग परीक्षण			
	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
पियर्सन काई वर्ग	56.427^{a}	12	.000
संभावना अनुपात परिक्षण	41.002	12	.000
लीनियर बाय लीनियर एसोसिएशन	49.012	1	.000
N of Valid Cases	400		
a. 5 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.52.			

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण के पश्चात् स्पष्ट होता है कि 0.05 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर शिक्षा का स्तर एवं शा. योजनाओं से लाभ प्राप्ति के पश्चात् जीवन स्तर में सामाजिक परिवर्तन के मध्य अन्तर संबंध की संरचना की स्थिति के मध्य कोई सार्थक संबंध नहीं है इसलिए शून्य परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शिक्षा का स्तर एवं शा. योजनाओं से लाभ प्राप्ति के पश्चात् जीवन स्तर में सामाजिक परिवर्तन के मध्य सार्थक संबंध है, जिसके कारण ग्रामीण उत्तरदाताओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में शासकीय योजनाओं के प्रभाव में सर्वाधिक ग्रामीण उत्तरदाताओं की संख्या 22.75 प्रतिशत है जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, एवं इन उत्तरदाताओं ने माध्यमिक तक शिक्षा प्राप्त की है, एवं इन उत्तरदाताओं का कहना है कि शा. योजनाओं से लाभ प्राप्ति के पश्चात् बच्चों की शिक्षा में परिवर्तन हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा है। तथा 3.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हाई सैकेण्डरी से अधिक शिक्षा प्राप्त की है और इन उत्तरदाताओं का कहना है कि शा. योजनाओं से लाभ प्राप्ति के पश्चात् सामान्य जीवन स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जो कि सबसे कम है।

पिछड़ी जनजातीय समुदाय की आयु एवं मनरेगा योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम के मध्य अन्तर संबंध की स्थिति :– अग्र तालिका में पिछड़ी जनजातीय समुदाय की

आयु एवं मनरेगा योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम के मध्य अन्तर संबंध को विश्लेषित किया गया है।

आयु	मनरेगा योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम					कुल
	तालाब निर्माण	तालाब गहरीकरण	सड़क निर्माण	डेमनिर्माण	नाली निर्माण	
25 वर्ष से कम	17 (4.25)	69 (17.25)	9 (2.25)	0 (0)	0 (0)	95 (23.75)
25 से 30 वर्ष	0 (0)	0 (0)	81 (20.25)	11 (2.75)	0 (0)	92 (23)
30 से 35 वर्ष	0 (0)	0 (0)	2 (0.5)	69 (17.25)	0 (0)	71 (17.75)
35 से 40 वर्ष	0 (0)	0 (0)	51 (12.75)	15 (3.75)	7 (1.75)	73 18.25
40 वर्ष से अधिक	0 (0)	5 (1.25)	20 (5)	31 (7.75)	13 (3.25)	69 (17.25)
कुल	**17** **(4.25)**	**74** **(18.5)**	**163** **(40.75)**	**126** **(31.5)**	**20** **(5)**	**400** **(100)**

स्त्रोतः– स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

उपरोक्त तालिका में आदिवासी समाज में मानवता का अध्ययन हेतु पिछड़ी जनजातीयों की आयु एवं मनरेगा योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम के मध्य अन्तर संबंध की संरचना की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पिछड़ी जनजातीय समुदाय के विकास में शासकीय योजनाओं के प्रभाव में सर्वाधिक 20.25 प्रतिशत है जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, एवं इन उत्तरदाताओं की आयु 25 से 30 वर्ष है, एवं इन उत्तरदाताओं का कहना है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत संचालित

कार्यक्रम सड़क निमार्ण का काम हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा है। तथा 17.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आयु 30 से 35 वर्ष से कम है, एवं इन उत्तरदाताओं का कहना है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम के अनुसार डेम निर्माण का काम हुआ है। 4.25 प्रतिशत ऐसे ग्रामीण उत्तरदाता है जिनकी आयु 25 वर्ष से कम है एवं इन उत्तरदाताओं का कहना है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम के अनुसार तालाब निर्माण का काम हुआ है। एवं 3.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आयु 40 वर्ष से अधिक है तथा इन उत्तरदाताओं का कहना है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम के अनुसार नाली निर्माण का काम हुआ है, जो कि सबसे कम है। अतः स्पष्ट है कि 20.25 प्रतिशत है जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, एवं इन उत्तरदाताओं की आयु 25 से 30 वर्ष है, एवं इन उत्तरदाताओं का कहना है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम सड़क निमार्ण का काम हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा है। तथा 3.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आयु 40 वर्ष से अधिक है तथा इन उत्तरदाताओं का कहना है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम के अनुसार नाली निर्माण का काम हुआ है, जो कि सबसे कम है।

उपरोक्त तालिका के पश्चात् पिछड़ी जनजातीयों की आयु एवं मनरेगा योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम के मध्य अन्तर संबंध की संरचना की स्थिति के मध्य स्वतंत्रता का परिक्षण करने के लिए काई वर्ग का परीक्षण किया गया है, जिसके अन्तर्गत शून्य परिकल्पना निम्नलिखित है। पिछड़ी जनजातीयों की आयु एवं मनरेगा योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम के मध्य अन्तर संबंध की संरचना की स्थिति के मध्य कोई सार्थक संबंध है। इस परिकल्पना के परिक्षण के लिए तालिका में दर्शाए गए आंकडों के अनुसार काई वर्ग का उपयोग करके जो परिणाम प्राप्त हुए है, उन्हें तालिका में दर्शाया गया है। काई वर्ग का परिक्षण में पिछड़ी जनजातीयों की आयु एवं मनरेगा योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम के मध्य अन्तर संबंध की संरचना की स्थिति :–

काई वर्ग का परिक्षण			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
पियर्सन काई वर्ग	56.795^a	16	.000
संभावना अनुपात परिक्षण	44.416	16	.000
लीनियर बाय लीनियर एसोसिएशन	16.335	1	.000
N of Valid Cases	400		
a. 10 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.93.			

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण के पश्चात् स्पष्ट होता है कि 0.05 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर पिछड़ी जनजातीयों की आयु एवं मनरेगा योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम के मध्य अन्तर संबंध की संरचना की स्थिति के मध्य सार्थक संबंध नहीं है इसलिए शून्य परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पिछड़ी जनजातीयों की आयु एवं मनरेगा योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम के मध्य सार्थक संबंध है, जिसके कारण ग्रामीण उत्तरदाताओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में शासकीय योजनाओं के प्रभाव में सर्वाधिक 20.25 प्रतिशत है जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, एवं इन उत्तरदाताओं की आयु 25 से 30 वर्ष है, एवं इन उत्तरदाताओं का कहना है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम सड़क निमार्ण का काम हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा है। तथा 3.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आयु 40 वर्ष से अधिक है तथा इन उत्तरदाताओं का कहना है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम के अनुसार नाली निर्माण का काम हुआ है, जो कि सबसे कम है।

पिछड़ी जनजातीयों का मुख्य व्यवसाय एवं वार्षिक आय के मध्य अन्तर संबंध की स्थिति :– अग्र तालिका में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली पिछड़ी जनजातीयों एवं वार्षिक आय के मध्य अन्तर संबंध को विश्लेषित किया गया है।

मुख्य व्यवसाय	वार्षिक आय					कुल
	30000 से कम	30000 से 40000	40000 से 50000	50000 से 60000	60000 से अधिक	
कृषि	10 (2.25)	41 (10.25)	35 (8.75)	5 (1.25)	4 (1)	95 (23.75)
मजदूरी	11 (2.75)	37 (9.25)	36 (9)	4 (1)	4 (1)	92 (23)
अशासकीय नौकरी	0 (0)	0 (0)	0 (0)	35 (8.75)	36 (9)	71 (17.75)
शासकीय नौकरी	0 (0)	3 (0.75)	3 (0.75)	34 (8.5)	33 (8.25)	73 (18.25)
व्यवसाय (धंधा)	0 (0)	27 (6.75)	25 (6.25)	8 (2)	9 (2.25)	69 (17.25)
कुल	**21** **(5.25)**	**108** **(27)**	**99** **(24.75)**	**86** **(21.5)**	**86** **(21.5)**	**400** **(100)**

स्त्रोतः– स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

उपरोक्त तालिका में आदिवासी समाज में मानवता का अध्ययन हेतु मुख्य व्यवसाय एवं वार्षिक आय के मध्य अन्तर संबंध की संरचना की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पिछड़ी जनजातीय समुदाय के विकास में शासकीय योजनाओं के प्रभाव में सर्वाधिक 10.25 प्रतिशत है जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, एवं इन उत्तरदाताओं की वार्षिक आय 30000 से 40000 तक है, जो कि सबसे ज्यादा है। तथा 9 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाता मजदूरी करते है तथा इन उत्तरदाताओं

की वार्षिक आय 40000 से 50000 तक है। 8.75 प्रतिशत ऐसे ग्रामीण उत्तरदाता है जो कि अशासकीय नौकरी करते एवं इन उत्तरदाताओं की वार्षिक आय 50000 से 60000 तक है। एवं 8.25 प्रतिशत उत्तरदाता शासकीय नौकरी करते है जिनकी वार्षिक आय 60000 से अधिक है, जो कि सबसे कम है। अतः स्पष्ट है कि 10.25 प्रतिशत है जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, एवं इन उत्तरदाताओं की वार्षिक आय 30000 से 40000 तक है, जो कि सबसे ज्यादा है। तथा 8.25 प्रतिशत उत्तरदाता शासकीय नौकरी करते है जिनकी वार्षिक आय 60000 से अधिक है, जो कि सबसे कम है।

उपरोक्त तालिका के पश्चात् मुख्य व्यवसाय एवं वार्षिक आय के मध्य अन्तर संबंध की संरचना की स्थिति के मध्य स्वतंत्रता का परिक्षण करने के लिए काई वर्ग का परीक्षण किया गया है, जिसके अन्तर्गत शून्य परिकल्पना निम्नलिखित है। मुख्य व्यवसाय एवं वार्षिक आय के मध्य अन्तर संबंध की संरचना की स्थिति के मध्य कोई सार्थक संबंध है। इस परिकल्पना के परिक्षण के लिए तालिका में दर्शाए गए आंकडों के अनुसार काई वर्ग का उपयोग करके जो परिणाम प्राप्त हुए है, उन्हें तालिका में दर्शाया गया है। काई वर्ग का परिक्षण में मुख्य व्यवसाय एवं वार्षिक आय के मध्य अन्तर संबंध की संरचना की स्थिति :–

काई वर्ग का परिक्षण

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
पियर्सन काई वर्ग	73.038[a]	16	.000
संभावना अनुपात परिक्षण	27.725	16	.000
लीनियर बाय लीनियर एसोसिएशन	55.062	1	.000
N of Valid Cases	400		

a. 5 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.62.

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण के पश्चात् स्पष्ट होता है कि 0.05 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर मुख्य व्यवसाय एवं वार्षिक आय के मध्य अन्तर संबंध की संरचना की स्थिति के मध्य सार्थक संबंध नहीं है इसलिए शून्य परिकल्पना को स्वीकार किया जाता

है, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मुख्य व्यवसाय एवं वार्षिक आय के मध्य सार्थक संबंध है, जिसके कारण ग्रामीण उत्तरदाताओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में शासकीय योजनाओं के प्रभाव में सर्वाधिक 10.25 प्रतिशत है जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, एवं इन उत्तरदाताओं की वार्षिक आय 30000 से 40000 तक है, जो कि सबसे ज्यादा है। तथा 8.25 प्रतिशत उत्तरदाता शासकीय नौकरी करते है जिनकी वार्षिक आय 60000 से अधिक है, जो कि सबसे कम है।

पिछड़ी जनजातीयों की आयु एवं जनजातियों के विकास योजनाओं का लाभ लिया है यदि हाँ तो किसके माध्यम से पता चला के मध्य अन्तर संबंध की स्थिति :— अग्र तालिका में पिछड़ी जनजातीयों की आयु एवं जनजातियों के विकास योजनाओं का लाभ लिया है यदि हाँ तो किसके माध्यम से पता चला के मध्य अन्तर संबंध को विश्लेषित किया गया है।

आयु	जनजातियों के विकास योजनाओं का लाभ					कुल
	मोबाईल एप	टी. वी.	रेडियो	मित्र एवं रिश्तेदारों से	समाचार पत्र	
25 से कम	4 (1)	69 (17.25)	5 (1.25)	0 (0)	0 (0)	78 (19.5)
25 से 30	13 (3.25)	0 (0)	96 (24)	15 (3.75)	0 (0)	124 (31)
30 से 35	0 (0)	0 (0)	1 (0.25)	69 (17.25)	0 (0)	70 (17.5)
35 से 40	0 (0)	0 (0)	43 (10.75)	15 (3.75)	7 (1.75)	65 (16.25)
40 से अधिक	0 (0)	5 (1.25)	18 (4.5)	27 (6.75)	13 (3.25)	63 (15.75)
कुल	**17** **(4.25)**	**74** **(18.5)**	**163** **(40.75)**	**126** **(31.5)**	**20** **(5)**	**400** **(100)**

स्त्रोतः— स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

उपरोक्त तालिका में आदिवासी समाज में मानवता का अध्ययन हेतु ग्रामीण आयु एवं जनजातियों के विकास योजनाओं का लाभ लिया है यदि हाँ तो किसके माध्यम से पता चला के मध्य अन्तर संबंध की संरचना की स्थिति का विश्लेषण किया

गया है। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पिछड़ी जनजातीय समुदाय के विकास में शासकीय योजनाओं के प्रभाव में सर्वाधिक 24 प्रतिशत है जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, एवं इन उत्तरदाताओं की आयु 25 से 30 वर्ष है, एवं इन उत्तरदाताओं का कहना है कि जनजातियों के विकास योजनाओं का लाभ रेड़ियों के द्वारा प्राप्त हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा है। तथा 17.5 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं की आयु 25 वर्ष से कम है जिनका कहना है कि जनजातियों के विकास योजनाओं का लाभ मोबईल एप के द्वारा प्राप्त हुआ है। 6.75 प्रतिशत ऐसे ग्रामीण उत्तरदाता है जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक है और इन उत्तरदाताओं का कहना की जनजातियों के विकास योजनाओं का लाभ दोस्त एवं रिश्तेदारों के द्वारा प्राप्त हुआ है, जो कि सबसे कम है। अतः स्पष्ट है कि 24 प्रतिशत है जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, एवं इन उत्तरदाताओं की आयु 25 से 30 वर्ष है, एवं इन उत्तरदाताओं का कहना है कि जनजातियों के विकास योजनाओं का लाभ रेड़ियों के द्वारा प्राप्त हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा है। तथा 6.75 प्रतिशत ऐसे ग्रामीण उत्तरदाता है जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक है और इन उत्तरदाताओं का कहना की जनजातियों के विकास योजनाओं का लाभ दोस्त एवं रिश्तेदारों के द्वारा प्राप्त हुआ है, जो कि सबसे कम है।

उपरोक्त तालिका के पश्चात् आयु एवं जनजातियों के विकास योजनाओं का लाभ लिया है यदि हाँ तो किसके माध्यम से पता चला के मध्य अन्तर संबंध की संरचना की स्थिति के मध्य स्वतंत्रता का परिक्षण करने के लिए काई वर्ग का परीक्षण किया गया है, जिसके अन्तर्गत शून्य परिकल्पना निम्नलिखित है। आयु एवं जनजातियों के विकास योजनाओं का लाभ लिया है यदि हाँ तो किसके माध्यम से पता चला के मध्य अन्तर संबंध की संरचना की स्थिति के मध्य कोई सार्थक संबंध है। इस परिकल्पना के परिक्षण के लिए तालिका में दर्शाए गए आंकडों के अनुसार काई वर्ग परीक्षण का उपयोग करके जो परिणाम प्राप्त हुए है, उन्हें तालिका में दर्शाया गया है। काई वर्ग परीक्षण का परिक्षण में आयु एवं जनजातियों के विकास योजनाओं का लाभ लिया है यदि हाँ तो किसके माध्यम से पता चला के मध्य अन्तर संबंध की संरचना की स्थिति :–

काई वर्ग परीक्षण			
	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
पियर्सन काई वर्ग	72.743[a]	16	.000
संभावना अनुपात परिक्षण	42.977	16	.000
लीनियर बाय लीनियर एसोसिएशन	47.031	1	.000
N of Valid Cases	400		
a. 8 cells (32.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.68.			

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण के पश्चात् स्पष्ट होता है कि 0.05 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर आयु एवं जनजातियों के विकास योजनाओं का लाभ लिया है यदि हाँ तो किसके माध्यम से पता चला के मध्य अन्तर संबंध की संरचना की स्थिति के मध्य सार्थक संबंध नहीं है इसलिए शून्य परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आयु एवं जनजातियों के विकास योजनाओं का लाभ लिया है यदि हाँ तो किसके माध्यम से पता चला के मध्य सार्थक संबंध है, जिसके कारण ग्रामीण उत्तरदाताओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में शासकीय योजनाओं के प्रभाव में सर्वाधिक 24 प्रतिशत है जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, एवं इन उत्तरदाताओं की आयु 25 से 30 वर्ष है, एवं इन उत्तरदाताओं का कहना है कि जनजातियों के विकास योजनाओं का लाभ रेड़ियों के द्वारा प्राप्त हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा है। तथा 6.75 प्रतिशत ऐसे ग्रामीण उत्तरदाता है जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक है और इन उत्तरदाताओं का कहना की जनजातियों के विकास योजनाओं का लाभ दोस्त एवं रिश्तेदारों के द्वारा प्राप्त हुआ है, जो कि सबसे कम है।

पिछड़ी जनजातीयों की आयु एवं जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न योजनायें बनाई है के मध्य अन्तर संबंध की स्थिति :– अग्र तालिका में पिछड़ी जनजातीयों की आयु एवं जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न योजनायें बनाई है के मध्य अन्तर संबंध को विश्लेषित किया गया है।

आयु	जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं					कुल
	प्रधानमंत्री ग्रामीन आवास योजना	मनरेगा योजना	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	राष्ट्रीय ग्रामीण आजिवीका मिशन योजना	अन्य योजनाए	
25 से कम	17 (4.25)	69 (17.25)	9 (2.25)	0 (0)	0 (0)	95 (23.75)
25 से 30	0 (0)	0 (0)	81 (20.25)	11 (2.75)	0 (0)	92 (23)
30 से 35	0 (0)	0 (0)	2 (0.5)	69 (17.25)	0 (0)	71 (17.75)
35 से 40	0 (0)	0 (0)	51 (12.75)	15 (3.75)	7 (1.75)	73 (18.25)
40 से अधिक	0 (0)	5 (1.25)	20 (5)	31 (7.75)	13 (3.25)	69 (17.25)
कुल	**17** **(4.25)**	**74** **(18.5)**	**163** **(40.75)**	**126** **(31.5)**	**20** **(5)**	**400** **(100)**

स्त्रोतः– स्वयं सर्वेक्षण पर आधारित समंक

उपरोक्त तालिका में आदिवासी समाज में मानवता का अध्ययन हेतु आयु एवं जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न योजनायें बनाई है के मध्य अन्तर संबंध की संरचना की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट होता है

कि पिछड़ी जनजातीय समुदाय के विकास में शासकीय योजनाओं के प्रभाव में सर्वाधिक 20.25 प्रतिशत है जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, एवं इन उत्तरदाताओं की आयु 25 से 30 वर्ष है, एवं इन उत्तरदाताओं का कहना है कि जनजातियों के विकास के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई गयी है, जो कि सबसे ज्यादा है। तथा 17.35 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं की आयु 25 वर्ष से कम है जिनका कहना है कि जनजातियों के विकास के लिए मनरेगा योजना बनाई गयी है। 7.75 प्रतिशत ऐसे ग्रामीण उत्तरदाता है जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक है और इन उत्तरदाताओं का कहना की जनजातियों के विकास के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजिवीका मिशन योजना बनाई गयी है, जो कि सबसे कम है। अतः स्पष्ट है कि 20.25 प्रतिशत है जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, एवं इन उत्तरदाताओं की आयु 25 से 30 वर्ष है, एवं इन उत्तरदाताओं का कहना है कि जनजातियों के विकास के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई गयी है, जो कि सबसे ज्यादा है। तथा 7.75 प्रतिशत ऐसे ग्रामीण उत्तरदाता है जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक है और इन उत्तरदाताओं का कहना की जनजातियों के विकास के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजिवीका मिशन योजना बनाई गयी है, जो कि सबसे कम है।

उपरोक्त तालिका के पश्चात् आयु एवं जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न योजनायें बनाई है के मध्य अन्तर संबंध की संरचना की स्थिति के मध्य स्वतंत्रता का परिक्षण करने के लिए काई वर्ग का परीक्षण किया गया है, जिसके अन्तर्गत शून्य परिकल्पना निम्नलिखित है। आयु एवं जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न योजनायें बनाई है के मध्य अन्तर संबंध की संरचना की स्थिति के मध्य कोई सार्थक संबंध है। इस परिकल्पना के परिक्षण के लिए तालिका में दर्शाए गए आंकडों के अनुसार काई वर्ग परीक्षण का उपयोग करके जो परिणाम प्राप्त हुए है, उन्हें तालिका में दर्शाया गया है। काई वर्ग परीक्षण का परिक्षण में आयु एवं जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न योजनायें बनाई है के मध्य अन्तर संबंध की संरचना की स्थिति :–

काई वर्ग का परिक्षण			
	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
पियर्सन काई वर्ग	56.795^{a}	16	.000
संभावना अनुपात परिक्षण	44.416	16	.000
लीनियर बाय लीनियर एसोसिएशन	16.335	1	.000
N of Valid Cases	400		
a. 10 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.93.			

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण के पश्चात् स्पष्ट होता है कि 0.05 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर आयु एवं जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न योजनायें बनाई है के मध्य अन्तर संबंध की संरचना की स्थिति के मध्य सार्थक संबंध है इसलिए शून्य परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आयु एवं जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न योजनायें बनाई है के मध्य सार्थक संबंध नहीं है, जिसके कारण ग्रामीण उत्तरदाताओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में शासकीय योजनाओं के प्रभाव में सर्वाधिक 20.25 प्रतिशत है जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, एवं इन उत्तरदाताओं की आयु 25 से 30 वर्ष है, एवं इन उत्तरदाताओं का कहना है कि जनजातियों के विकास के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई गयी है, जो कि सबसे ज्यादा है। तथा 7.75 प्रतिशत ऐसे ग्रामीण उत्तरदाता है जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक है और इन उत्तरदाताओं का कहना की जनजातियों के विकास के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजिवीका मिशन योजना बनाई गयी है, जो कि सबसे कम है।

निष्कर्ष :— प्रस्तुत शोध अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण क्षेत्र में शासन द्वारा चलाई जा रही शासकीय योजनाओं से आदिवासियों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है तथा वार्षिक आय में वृद्धि हुई है, रोजगार में वृद्धि हुई है। एवं ग्रामीण आदिवासियों को सरकार के द्वारा आवास के लिए अनुदान राशि भी दी जाती है। तथा ग्रामीण आदिवासियों को सरकार के द्वारा शासकीय योजनाओं से संबंधित योजनाओं की जानकारी समय—समय पर दी जाती है। शासकीय योजनाओं की जानकारी प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सेवक, रेड़ियों, टी.वी., समाचार—पत्र के द्वारा पहुंचायी जाती है। तथा प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाई जा रही शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जिससे ग्रामीण आदिवासियों को अन्य साधनों के द्वारा रोजगार प्राप्त हो रहा है, शासकीय योजनाओं से ग्रामीण आदिवासियों के भौतिक साधनों में भी वृद्धि हो रही है। तअतः इससे यह स्पष्ट होता है कि शासकीय योजनाओ का ग्रामीण आदिवासियों पर प्रभाव पडा है।

समस्याऐं :—

1. पिछडी जनजातीयों को आवंटन देने में अत्यधिक विलंब करते है।
2. पिछडी जनजातीयों को प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त की राशि समय पर नहीं मिलती है।
3. पिछडी जनजातीयों को प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि कम मिलती है।
4. पिछडी जनजातीयों को मनरेगा में प्रति व्यक्ति 100 दिन का रोजगार प्राप्त होता है जो सभी ग्रामीण नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है।
5. पिछडी जनजातीयों में जागरूकता की कमी ।
6. पिछडी जनजातीयों को मनरेगा के तहत अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते है।
7. पिछडी जनजातीयों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सब्सिडी की लागत ज्यादा होना।
8. पिछडी जनजातीयों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर निकालने की जानकारी न होना।

9. पिछडी जनजातीयों को स्वयं–सहायता समूह में महिलाओं के लिए और ऋण की व्यवस्था नहीं ।

10. पिछडी जनजातीयों को स्वयं–सहायता समूह में महिलाओं के लिए और ऋण की राशि जमा करने के लिए समय अवधि बहुत कम है।

सुझाव :–

1. स्वयं सहायता समूह में ऋण की राशि बढ़ाना चाहिए।

2. स्वयं सहायता समूह में ऋण की राशि जमा करने के लिए समय अवधि और बढ़ाना चाहिए।

3. स्वयं सहायता समूह में बैठक व्यवस्था होनी चाहिए।

4. आवास से संबंधित समस्या का समाधान करना चाहिए।

5. आवंटन की राशि बढ़ाना चाहिए।

6. आवंटन की राशि समाय पर प्राप्त होनी चाहिए।

7. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सब्सिडी की लागत कम होनी चाहिए।

8. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर निकालने की जानकारी देना चाहिए।

9. जागरूकता की कमी

10. मनरेगा के तहत अपने अधिकारों के बारे में जानकारी देना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

क्रमांक	लेखक का नाम, वर्ष, शीर्षक, प्रकाशन, अंक, पृष्ट संख्या
1.	गांवों से पलायन का बदलता स्वरूप मधुकर कोटवे 3–6
2.	गांवों से पलायन की बढ़ती प्रवृत्ति चुनौतियां एवं समाधान डॉ. अनीता मोदी 7–9
3.	पलायन समस्या या सामान्य मानवीय प्रक्रिया सुभाष सेतिया 10–13
4.	गांवों से पलायन : कारण एवं निवारण प्रतापमल देवपुरा 14–16
5.	ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन : कारण एवं परिणाम डॉ. अर्जुन सोलंकी 17–21
6.	रोजगार नहीं होना पलायन का मुख्य कारण विकास कुमार सिन्हा 22–28
7.	पलायन : गरीबी और बेरोजगारी सुनील कुमार ठाकुर 29–32
8.	बुन्देलखण्ड के गांवों में रोजगार संकट से बढ़ता पलायन सुन्दर सिंह राणा 33–36
9.	यूनेस्को के एक अध्ययन से पता चलता है कि मौसमी प्रवास ज्यादातर अशिक्षित और एस.सी., एस.टी. वर्गों में अधिक पाया जाता है (मरीना और तनखा, 2013, पेज, 15)
10.	राव और फिनॉफ " भारत में अब महिलाओं के पलायन के प्रमुख कारणों में शादी के कारण में गिरावट आई है तथा तब महिलाओं के पलायन का कारण आर्थिक कारण अधिक है" (2015)
11.	मयंक श्रीवास्तव "ग्रामीण भारत की बदलती तस्वीर" कुरूक्षेत्र (2013)
12.	राजू कुमार "ग्रामीण विकास के लिए जागरूक समूह" कुरूक्षेत्र (2013)
13.	पंकज चतुर्वेदी "ग्रामीण विकास की छ.ग. तस्वीर" कुरूक्षेत्र (2013)

14.	आर. सिंह ’’समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का ग्रामीण विकास पर प्रभाव’’ कुरूक्षेत्र (2013)
15.	रतन जगन्नाथ ’’ग्रामीण विकास और वित्तीय समावेशन’’ कुरूक्षेत्र (2012)
16.	सुरेन्द्र बहादुर सिंह ’’ पंचायतती राज से बेहतर हुआ ग्रामीण प्रशासन’’ (2011)
17.	आसुतोष शुक्ला ‘‘भारत की अधिकांश जनता गाँवों में रही है’’ कुरूक्षेत्र (2011)
18.	त्रिपाठी रामदत्त ’’पंचायतों में पैसा है, पर कर्मचारी नहीं,, योजना पत्रिका (2010)
19.	डॉ. जगबीर कौशिक ‘‘किसी देश का विकास तब तक सम्भव नहीं है’’ योजना पत्रिका (2010)
20.	हरिराम पाण्डे ’’भारत का विचार और ग्राम विकास’’ योजना पत्रिका (2010)
21.	डॉ. हनुमतं यादव ’’दक्षिण कोरिया में ग्राम विकास’’ योजना पत्रिका (2010)
22.	देवेन्द्र उपाध्याय ’’पंचायत राज और महिला संस्कृतिकरण’’ योजना पत्रिका (2010)
23.	सुरेन्द्र सिंह चौहान ’’ ऐसे होगा गाँव का संमग्र विकास’’ वार्षिक रिपोर्ट (2009)
24.	भैया जी जोशी लेख ’’ग्रामीण विकास की संकल्पना आत्मनिर्भर’’ योजना पत्रिका (2009)
25.	डॉ. सुधीश कुमार पटेल ’’पंचायती राज में रोजगार’’ कुरूक्षेत्र (2009)
26.	लोकेश कुमार ’’गाँवों को विकास की ओर ले जाती पंचायते’’ कुरूक्षेत्र (2009)
27.	डॉ. रमन, सिंह ने अपने लेख में तेजी से साकार हो रहा है पंचायती राज का सपना’’ कुरूक्षेत्र (2009)
28.	स्वाति शर्मा ’’ भारत में ग्रामीण विकास एवं चिंता’’ कुरूक्षेत्र (2008)
29.	विमल कुमार सिंह ‘‘ग्राम विकास और अप्रवासी’’ कुरूक्षेत्र (2005)
30.	डॉ. राजेश ‘‘ग्राम विकास में पंचायतों का योगदान’’ कुरूक्षेत्र (2005)

31.	त्रिपाठी रामदत्त ''पंचायतों में पैसा है, पर कर्मचारी नहीं'' कुरूक्षेत्र (2010)
32.	खान नजमा, (1982), "पैटर्न ऑफ रूरल ऑउटमाईग्रेशन, एक माईक्रो स्टडी", बी.आर. पब्लिशिंग कॉपरेशन, दिल्ली।
33.	हसनैन, नदीम – जनजातीय भारत, पृ. 168
34.	हसनैन नदीम, जनजातीय भारत, जवाहर पब्लिशर्स ऐंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली 2010
35.	प्रियंका शर्मा, (2013) ''वुमन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इंडिया'', ग्लोबल जर्नल ऑफ़ मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टडीज़। खंड 3, संख्या 4, पीपी 371–376।
36.	शर्मा, बिमला चरण (2011) : झारखण्ड : भूमी और भूमीपुत्र, झारखण्ड झरोखा राँची।
37.	डॉ. दिनेश कुमार तीवारी (2002) ''बारेला जनजाति के प्रवासित परिवारों का सामाजिक–आर्थिक अध्ययन'' (बुंदेलखण्ड क्षेत्र के विशेष सन्दर्भ में)।
38.	डॉ. अशोक डी पाटील म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल।
39.	राव देवेन्द्र बाबु, शेड्यल कास्ट एण्ड ट्राइब्स सोसियों इकॉनामी, 1999 नई दिल्ली।
40.	शर्मा ब्रह्मदेव (1980) आदिवासी विकास– एक सैद्धांतिक विवेचन मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
41.	**केसरी, कमल और आर. बी. भगत, इन** ''टेम्परेरी एन्ड सीजनल माइग्रेसन : रीजनल पैटर्न, कैरक्टेरिक्टिकय एंड एसोसिएटेड फैक्टर्स'', ई. पी. डब्ल्यू, जनवरी, 28, 2012, वोल्यमू –47, नं. 4, पजे 81–88.
42.	**रॉय, शमिन्द्र एन्ड मनीष मुक्त नायक**– ''माइग्रेंट्स इन कंसट्रक्शन वर्क : इवेल्यूएटिंग देयर वेल्फेयर फ्रेमवर्क'', सेंटर फॉर पोलिसी रिसर्च, जून 2017.

43.	CHAUDHARY, D. K. (2021). UNEMPLOYMENT STATUS IN VAISHALI DISTRICT OF BIHAR-A SOCIO- ECONOMIC PERSPECTIVE.
44.	Kumar, A., & Kumar, M. (2020). Marginalised Migrants and Bihar as an Area of Origin. *Kerala Exp*, *55*, 21.
45.	https://www.un.org/en/sections/issues-depth/migration/index.html, United Nations official website.
46.	Ernst & Young, NASSCOM and FICCI. (2017). Future of jobs in India. A 2022 perspective. Available online at: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-future-of-jobs-in-india/%24FILE/ey-future-of-jobs-in-india.pdf - Accessed on 27 February 2019.
47.	आदिवासी दुनिया, हरिराम मीणा, नेशनल बुक ट्रस्ट, 2013, पृ. 168.
48.	आदिवासी दुनिया : हरिराम मीणा, पृ. 169.
49.	आदिवासी साहित्य विमर्श, गंगासहाय मीणा, पृ. 19.
50.	आदिवासी अस्मिता के प्रश्न, रमणिका गुप्ता, हाशिये का वृत्तांत, संपा. दीपक वुफमार, देवन्द्र चौबे, पृ. 353.
51.	भारतीय जनजातियाँ, रूपचन्द्र वर्मा, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, 2003, पृ. 46.
52.	जनजातीय भारत, नदीम हसनैन, जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 2002, पृ. 265.
53.	आदिवासी अस्मिता के प्रश्न, रमणिका गुप्ता, हाशिये का वृत्तांत, संपा. दीपक कुमार, देवेन्द्र चौबे, पृ. 357. वही, पृ. 357–358.
54.	आदिवासी अस्मिता के प्रश्न, रमणिका गुप्ता, पृ. 351.
55.	रावत, डॉ0 रूकमा (1997), रिटर्न माइग्रेशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट, सिद्धि पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, टिहरी गढ़वाल।

56.	जॉर्ज फिलिप द्वारा (1982), “बर्थ डेथ एण्ड मॉइग्रेशन इन हिमालयास”, भारी पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
57.	प्रभाकर, एन. आर. (1985),”इनटरनल माइग्रेशन एण्ड पॉपुलेशन रिड्रीस्टीब्यूशन इन इण्डिया“, कानसेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली।
58.	चैरूनील, फ्रान्सिस, (1987) ”पलायन, सेन्सस कोरलेट्स कॉनसिक्यावनसेस ट्रडस एण्ड पॉलिसिस, हिमालया पब्लिशिंग हॉउस, दिल्ली।
59.	रावत, पी. एस. (1993), “मागइग्रेशन एण्ड स्ट्रक्चरल चेंज ए स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटी इन गढ़वाल हिमालय”, प्रकाशन सरीता बुक हाउस, दिल्ली (भारत)
60.	mÙkjk[k.M dh xzke iapk;rksa esaa izoklu dh fLFkfr ij vafre fjiksVZ] iyk;u vk;ksx ¼vizSy] 2018½
61.	चौधरी, पदम सिंह, (2012) कुरूक्षेत्र, Publications Division, Min. of Information & Broadcasting , East Block-IV, Level-VII, R.K. Puram, New Delhi
62.	पुराणिक आलोक, आर्थिक पत्रकारिता, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2007
63.	नैयर डॉ. रेणुका, ग्रामीण क्षेत्र की पत्रकारिता, हरियाणा साहित्य अकादमी,2002
64.	सिंह एम.के झारखण्ड विकास एवं राजनीति, गगनदीप पब्लिकेशनस, दिल्ली, 2007
65.	सिंह कुमार अजय, मीडिया इतिहास और हासिये के लोग, आधार प्रकाशन प्रा. लि. पंचकूला, हरियाण, 2007
66.	चोपड़ा लक्ष्मेन्द्र, मीडिया और समाज, आधार प्रकाशन प्रा. लि. पंचकूला,हरियाणा, 2006

67.	भारत 2010—प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
68.	जोशी रामशरण, आदमी, बैल और सपने कल्याणी शिक्षा परिशद, दिल्ली 2008
69.	वैकल्पिक आर्थिक वार्षिकी—3— वैकल्पिक सर्वे समूह इंडियन पोलिटिकल इकॉनमी एसोसिएशन—युवा संवाद प्रकाशन, दिल्ली
70.	मेहता, प्रकाशचंद्र (2009) आदिवासी संस्कृति एवं प्रथाएँ, डिसकवरी पब्लिशिंग हाउस प्रा0 लि0 नई दिल्ली।
71.	केसरी, विसेश्वरी प्रसाद (1979) : छोटानागपूर का इतिहास, विलियम कैरी स्टडी एण्ड रिसर्च सेन्टर। सिरानपुर (कलकत्ता)।
72.	वासवी, (2003) : ताबेनजोम जमीन का हिस्सा, आधार प्रकाशन, पंचकुला (हरियाणा)
73.	उर्मीलेश (1999) : झारखण्ड जादूई जमीन का अंधेरा, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली।
74.	साहु, चतुर्भुज (2007) : झारखण्ड की जनजातियाँ, के0 के0 पब्लिकेशन, इलाहाबाद।
75.	मुण्डा, रामदयाल (2002) : आदिवासी अस्तित्व और झारखण्डी अस्मिता के सवाल, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली।
76.	मुण्डा, सुभाष चंद्र (2003) : पंचपरगना के मुण्डाओं पर हिन्दू धर्म का प्रभाव, कैलाश पेपर कन्वर्सन प्रा0 लि0 बुण्डु।
77.	अनुज भुवनेश्वर (2002) : अतीत के दर्पण मे झारखण्ड, नॉवल्टी आर्ट प्रेस, मेन रोड राँची।
78.	समयांतर मासिक पत्रिका—संपादक, पंकज विष्ट, 79—ए, दिलशाद गार्डेन,

	नई दिल्ली, अंक : अगस्त 2010,
79.	रमणिका गुप्ता–आदिवासी : साहित्य यात्रा, रमणिका फाउंडेशन, राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा0लि0, नई दिल्ली, पहला संस्करण : 2008
80.	लीलाधर शर्मा 'पर्वतीय'–भारतीय संस्कृति कोश, राजपाल एण्ड सन्ज, कश्मीरी गेट, नई दिल्ली, पहला संशोधित संस्करण : 1996
81.	रमणिका गुप्ता–आदिवासी कौन?, रमणिका फाउंडेशन, राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा.लि., नई दिल्ली, पहला संस्करण : 2008
82.	डॉ. मिश्र जगनाथ – भारतीय आर्थिक विकास की नयी प्रवृतियॉ, विकास पब्लिकेशन हाउस,दिल्ली,
83.	उपाध्याय विजय शंकर, वर्मा विजय प्रकाश–भारत की जनजातीय संस्कृति, मध्यप्रदेश हिंन्दी ग्रंथ अकादमी, पंचम आवृत्ति : 1998
84.	रमणिका गुप्ता–आदिवासी : विकास से विस्थापन, रमणिका फाउंडेशन, राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा0लि0, नई दिल्ली, पहला संस्करण : 2008
85.	डॉ. मामोरिया एवं जनै – भारतीय अर्थशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा,
86.	डॉ. आर.एन. त्रिवेदी – रिसर्च मैथ्डोलाजी, कालेज बुक डीपोट,जयपुर,
87.	डॉ. संजय तिवारी – सामाजिक विज्ञान में शोध प्रविधी, साहित्य भवन, आगरा
88.	डॉ. वी.सी. सिन्हा – भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सांख्यिकी, एस.बी.डी.पी. पब्लिशिंग हाउस,मथुरा
89.	महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम

90. डॉ. श्यामाचरण दुबे, म.प्र. आदिवासी अनुसंधान परिषद्, भोपाल।

91. रिजले हर्बर्ट, द पिपुल्स ऑफ इंडिया,(1891)

92. एस.सी. वर्मा ''दी भील किल्स'' कुंज पब्लिक हाउस दिल्ली 1978।

93. मेहता प्रकाशचन्द्र (1993) भारत के आदिवासी– एक सामाजिक आर्थिक विवेचन, शिवा पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्युटर्स, उदयपुर।

94. श्रीवास्तव, प्रदीप 1999 भारत का जनजातीय जनजीवन मानव शास्त्र प्रियंका पब्लिकेशन, बिलासपुर।

95. तिवारी शिवकुमार (1984) मध्यप्रदेश के आदिवासी, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।

96. ली, इवरेट, ''ए थ्योरी ऑफ माइग्रेसव'', डेमोग्रेफी, 1996, वॉ. 3, न. पे. 47–57।

97. मजूमदार, इंद्राणी, एन. नीक्षा, एण्ड इंदू अग्निहोत्री, – ''माइग्रेसन एण्ड जेन्डर इन इंडिया, ''ई.पी.डब्ल्यू., मार्च 9, 2013, वोल्यूम, 48, नं. 10, पेज 54–64.

98. मुखर्जी, राहुल, 2014 – पोलिटिकल इकोनोमी ऑफ रिफार्मस इन इंडिया, न्यू–दिल्ली, ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी प्रेसमुनक,

99. रिवेंसटीन, ई. जी, – ''द लॉज ऑफ माइग्रेसन'', जर्नल ऑफ द रॉयल स्टेटिस्टिकल सोसाइटी, जून 1889, वोल्यूम 52, नं. 2, पेज 241–305.

100. राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर, उदयपुर संस्करण, 22 मार्च, 2017